हम धार्मिक रूप से प्रताड़ित हर एक अल्पसंख्यक शरणार्थी को नागरिकता देकर रहेंगे

सर्व सहकार सर्व साकार

सहकार जागरण

वर्ष : 03 – अंक : 12 – मार्च 2026

सहकारिता से जुड़ेगी देश की 40 प्रतिशत आबादी

राज्यों के सहकारिता मंत्रियों के साथ केंद्रीय सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह की मंथन बैठक

बंद चीनी मिलों को शुरू करें राज्य सरकारें

अन्न भंडारण में बढ़े सहकारिता की हिस्सेदारी

भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ

सर्व सहकार सर्व साकार
सहकार जागरण
मार्च 2026, अंक 12, वर्ष 03

संपादक मंडल

संपादक
राजीव शर्मा

सहकार जागरण से जुड़ी प्रतिक्रिया, सुझाव या आलेख देना चाहते हैं तो हमें ई-मेल करें:
sahakarjagran@gmail.com
ncui.pub@gmail.com
प्रकाशन का अंतिम निर्णय संपादक मंडल का होगा।
निदेशक (प्रकाशन/जनसंपर्क),
एनसीयूआई
एनसीयूआई कैंपस, 3, अगस्त क्रांति मार्ग, सिरी इंस्टीट्यूशनल एरिया, हौज खास, नई दिल्ली : 110016

सहकार जागरण से जुड़ने के अन्य पते:

MINISTRY OF COOPERATION

NCUI हाट

CEAS-LMS

भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ द्वारा 'सहकार जागरण' पत्रिका का सम्पादन एवं प्रकाशन किया जाता है, और इस पत्रिका के प्रकाशन के किसी भी हिस्से की सामग्री की प्रतिलिपि, पुनः उत्पादन या पुनर्वितरण संपादक पैनल और सामग्री के लेखक/लेखकों जैसा भी लागू हो, उनकी लिखित सहमति के बिना कोई भी व्यक्ति, संगठन या पार्टी नहीं कर सकती है। पत्रिका में प्रदर्शित सामग्री तथा आंकड़ें प्राथमिक और अनुषंगी स्रोतों (उद्योग विशेषज्ञ, अनुभवी व्यक्तियों, सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार आदि) से लिए गए हैं। पत्रिका में उपलब्ध आंकड़ों और रिपोर्टों के स्रोतों के संबंध में, न तो भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ और न ही इसके कर्मचारी किसी भी त्रुटि के लिए जिम्मेदार हैं और न ही इस संबंध में उनका कोई कानूनी दायित्व है।

आवरण कथा

06 सहकारिता से जुड़ेगी देश की 40 प्रतिशत आबादी

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह सहकारिता को विकसित भारत का आधार बनाने के लिए लगातार प्रयासरत हैं क्योंकि वह जानते और मानते हैं कि भारत के हर परिवार, हर व्यक्ति को सम्मान के साथ जीने का माध्यम सिर्फ और सिर्फ सहकारिता ही बन सकती है।

10 राज्य के साथ मिलकर हर गांव की कोऑपरेटिव को मजबूत करेंगे: श्री अमित शाह

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार पूरे देश की समृद्धि के लिए अहर्निश प्रयास कर रही है। किसानों के हितों की सुरक्षा और कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भरता सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

भारत टैक्सी: सारथियों की कहानी, उन्हीं की जुबानी 12

बस्तर देश का सबसे समृद्ध आदिवासी संभाग बनेगा 14

सिख आस्था के सम्मान के साथ ही प्रगति के नए अवसर सृजित कर रही सरकार 20

दसों गुरुओं के जीवन से प्रेरणा लेकर धर्म परिवर्तन के विरुद्ध सभी देशवासियों को एकजुट होना चाहिए 21

हम धार्मिक रूप से प्रताड़ित हर एक अल्पसंख्यक शरणार्थी को नागरिकता देकर रहेंगे 24

कृषि को मजबूती देने से किसानों को मिली आर्थिक सुरक्षा : प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 27

28 सहकारिता में सुधारों को मिल रही गति

भारत के विकास में सहकारिता की बड़ी भूमिका

देश में सहकारी आंदोलन ग्रामीण भारत में सामाजिक-आर्थिक विकास के एक सुदृढ़ माध्यम के रूप में स्थापित हो रहा है। पिछले चार वर्षों के दौरान केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय के सौ से अधिक व्यापक बुनियादी सुधारात्मक पहलों एवं नीतिगत बदलावकारी योजनाओं और नई सहकारिता नीति का प्रभाव गांवों के समग्र विकास और ग्रामीणों की आर्थिक उन्नति के रूप में फलीभूत हो रही है। इन सभी गतिविधियों को देश के सभी राज्यों में व्यावहारिक रूप से प्रभावी बनाने और सहकारिता को विकासित भारत का एक सशक्त माध्यम बनाने के लिए केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुजरात की राजधानी गांधीनगर में सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के सहकारिता मंत्रियों के साथ मंथन बैठक की। 'सहकार से समृद्धि' के संकल्प को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि इस मंथन बैठक का आयोजन इसीलिए हो रहा है कि हम 2047 में भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं। एक पूर्ण विकसित भारत का अर्थ है कि हमें ऐसी व्यवस्था करनी है जहां सभी 140 करोड़ देशवासी सम्मान के साथ जी सकें और देश के हर परिवार और हर व्यक्ति को सम्मान के साथ जीने की ऐसी सुचारू व्यवस्था तो सिर्फ और सिर्फ सहकारिता ही बन सकती है।

सहकारिता की समाज में स्वीकृति को बढ़ाने पर जोर देते हुए श्री शाह ने कहा कि आने वाले दिनों में अन्न भंडारण की व्यवस्था लगभग तीन गुना बढ़ाने की जरूरत है, जिसमें से दो गुना सहकारिता क्षेत्र को करनी चाहिए। यह सभी की जिम्मेदारी है, जिसे केवल पैक्स पर न छोड़कर तहसील की कोआपरेटिव डेयरियों से लेकर राज्य स्तर के मार्केटिंग फेडरेशन तक सभी को सबको बड़े-बड़े गोदाम बनाना चाहिए। इससे पूरे देश भर में अन्न भंडारण की एक सुचारू व्यवस्था बनेगी। इसी तरह, सभी राज्यों में बंद पड़ी सहकारी चीनी मिलों को भी शुरू करने और अन्य व्यावहारिक प्रयासों के माध्यम से किसानों की आर्थिक उन्नति की राह बनानी होगी।

सहकारिता प्राचीन समय से ही हमारी कार्य संस्कृति का अंग रही है। ग्रामीण भारत के जन-जीवन में इसकी अहम भूमिका, अर्थतंत्र में सहकारिता की बढ़ती भागीदारी और लंबे समय से स्वतंत्र सहकारिता मंत्रालय की हो रही मांग को ध्यान में रखकर ही प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने की सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की, जो पिछले चार वर्षों में अपनी बहुआयामी पहलों और पारदर्शी सुधार प्रकिया के माध्यम से सहकारी आंदोलन को देशव्यापी स्वरूप प्रदान कर रहा है।

सहकारिता मंत्रालय ने देश के सहकारिता क्षेत्र को आगे बढ़ाने के जो प्रयास किए हैं, उसके परिणाम अब समाज में दिखने लगे हैं। यह एक प्रामाणिक सत्य है कि कृषि, ग्रामीण विकास और पशुपालन क्षेत्रों को मजबूत किए बिना देश का सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता है। ऐसे में, सहकारिता के माध्यम से समाज को ग्रामीण समाज को आर्थिक रूप से समर्थ और सशक्त बनाने के अभियान को सफल बनाने की दिशा में प्रयास तेज किए गए हैं। कोआपरेटिव सेक्टर में बहुत सी नई सहकारी गतिविधियां शुरू की गई है, जो ग्रामीण व शहरी युवाओं को भी सहकारी क्षेत्र से जुड़ने और इस क्षेत्र में अपना करियर बनाने को प्रेरित कर रही हैं, क्योंकि सहकारिता क्षेत्र में रोजगार के लाखों नए अवसर सृजित हो रहे हैं। इस तरह, सहकारिता अब कारपोरेट जगत के प्रतिस्पर्धी बनने की राह पर आगे बढ़ रहा है।

जय सहकार

बीते 11 वर्षों में हमने अपनी मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्ट्स की क्वालिटी और अर्थनीति को फोकस में रखते हुए भारत को दुनिया का ग्रोथ इंजन बनाया है। हमारा यही सामर्थ्य है कि आज दुनिया के विकसित देश भी भारत के साथ ट्रेड डील करने के लिए खुद आगे आ रहे हैं।

श्री नरेन्द्र मोदी
प्रधानमंत्री

विश्व भर में भारत का गौरव बढ़ाने वाला 'डिजिटल इंडिया' अब गरीबों को पारदर्शी तरीके से सस्ता अनाज देने का माध्यम बनेगा। जो पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना देश के गरीबों के कल्याण का माध्यम बनी है, वह टेक्नोलॉजी से संपन्न होकर और भी अधिक पारदर्शी बनने जा रही है।

श्री अमित शाह
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री

सहकारी चुनाव प्राधिकरण ने अब तक लगभग 240 चुनाव सफलतापूर्वक संपन्न किए हैं और लगभग 70 चुनाव अभी चल रहे हैं। प्राधिकरण को अगले वित्तीय वर्ष में लगभग 130 चुनाव संपन्न कराने की उम्मीद है। हमारी सरकार सामाजिक सशक्तीकरण के पूर्ण उद्देश्य से सुधार लाने के लिए प्रतिबद्ध है।

श्री कृष्ण पाल गुर्जर
केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री

नारी केवल सृजन की शक्ति ही नहीं, बल्कि समाज, संस्कृति और राष्ट्र निर्माण की प्रेरक शक्ति भी है। अपने साहस, संवेदना, परिश्रम और नेतृत्व से महिलाएं हर क्षेत्र में नई ऊंचाइयां हासिल कर रही हैं और भारत के विकास को नई दिशा दे रही हैं।

श्री मुरलीधर मोहोल
केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री

सहकारिता मंत्रालय द्वारा किसानों की आर्थिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सहकारी संस्थाओं के माध्यम से सुलभ एवं किफायती ऋण उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण पहलें की गई हैं। सहकारी बैंकों और पैक्स के माध्यम से किसानों को समयबद्ध ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे वे बीज, उर्वरक और कृषि उपकरण जैसे आवश्यक संसाधन आसानी से प्राप्त कर सकें। यह व्यवस्था किसानों को वित्तीय संबल प्रदान करते हुए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी सशक्त बना रही है।

सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार

नई दिल्ली में एक मीडिया हाउस के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी बोले

हमारा एक ही लक्ष्य, एक ही मंजिल-विकसित भारत

सहकार जागरण टीम

भारत के स्वतंत्रता संग्राम तथा एक विकसित राष्ट्र बनने की उसकी वर्तमान यात्रा के बीच एक समानता है। जिस प्रकार आजादी को हासिल करने के लिए उस दौर में लोग एकजुट हुए थे, उसी प्रकार इस समय हमारा और 140 करोड़ भारतीयों का एक ही लक्ष्य व एक ही मंजिल है 'विकसित भारत'। हम भारतीय एक बार फिर 'विकसित भारत' (समृद्ध भारत) के निर्माण की एक नई यात्रा पर निकल पड़े हैं। ये बातें प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने नई दिल्ली में आयोजित एक मीडिया हाउस के कार्यक्रम में कही।

भारतीय नागरिकों में दिख रहे बेमिसाल आत्मविश्वास और आकांक्षाओं का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत सिर्फ तरक्की ही नहीं कर रहा है, भारत अब 'अगले पड़ाव' की ओर बढ़ रहा है। जब पूरी दुनिया की नजर भारत की प्रगति पर है, तो इस गति को बनाए रखने की सभी नागरिकों की सामूहिक जिम्मेदारी और भी बढ़ गई है। पीएम मोदी ने कहा कि यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) के तेज विकास ने देश के वित्तीय तंत्र को एक नए दौर में पहुंचा दिया है। इससे भारत रियल-टाइम डिजिटल लेन-देन में दुनिया का अग्रणी देश बन गया है। भारत ने अंतरिक्ष, सेमीकंडक्टर और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसे क्षेत्रों में खास मिशनों के जरिए नई ऊंचाइयों को छूकर पिछली तकनीकी सीमाओं को तोड़ दिया है। आज मून मिशन, सेमीकंडक्टर मिशन और क्वांटम मिशन भारत को टेक्नोलॉजी के अगले पड़ाव की ओर ले जा रहे हैं। भारत की प्रगति अब केवल क्रमिक नहीं, बल्कि प्रकृति में परिवर्तनकारी है।

भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता की रणनीतिक जरूरत को

- पूरी दुनिया बहुत उम्मीद के साथ देख रही है भारत की ओर
- ऊर्जा सुरक्षा की ओर मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा भारत

अहम बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने पिछले कई सालों में भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और बाहरी झटकों के प्रति उसकी कमजोरी को कम करने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण अपनाया है। प्रधानमंत्री ने पेट्रोलियम पर निर्भरता कम करने के मुख्य साधन के तौर पर इथेनॉल और बायोफ्यूल पर सरकार के रणनीतिक फोकस को रेखांकित करते हुए बताया कि 2014 से पहले ब्लेंडिंग क्षमता महज 1-1.5 प्रतिशत थी, जो आज बढ़कर लगभग 20 प्रतिशत हो गई है। इस पहल की वजह से पिछले 11 वर्षों में 18 करोड़ बैरल अतिरिक्त तेल खरीदने की जरूरत नहीं पड़ी। इस बदलाव की वजह से भारत अपने सालाना तेल आयात में लगभग 4.5 करोड़ बैरल की कमी कर पा रहा है। सिर्फ इथेनॉल ब्लेंडिंग से ही देश ने लगभग डेढ़ लाख करोड़ रुपए बचाए हैं।

रेलवे के विद्युतीकरण और नवीनीकरण ऊर्जा से राष्ट्रीय ईंधन बचत पर पड़ने वाले असर का जिक्र करते हुए श्री मोदी ने बताया कि जहां 2014 तक रेल नेटवर्क का सिर्फ 20 प्रतिशत हिस्सा ही विद्युतीकृत था, वहीं अब ब्रॉड-गेज नेटवर्क का लगभग 100 प्रतिशत हिस्सा बिजली से चलता है। हरित ऊर्जा क्रांति पर और जोर देते हुए प्रधानमंत्री ने बताया कि भारत की नवीनीकरण क्षमता ऐतिहासिक रूप से 250 गीगावाट तक पहुंच गई है। इससे अकेले सोलर पावर की क्षमता 2014 के दो गीगावाट से बढ़कर आज 130 गीगावाट हो गई है। 'पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना' ने 30 लाख परिवारों को रूफटॉप सोलर की मदद से अपने घरेलू ऊर्जा इस्तेमाल को बिजली की ओर मोड़ने के लिए सशक्त बनाया है। हमारी कुल नवीनीकरण क्षमता 250 गीगावाट के ऐतिहासिक आंकड़े को पार कर गई है। हमारी कुल स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता का आधा हिस्सा अब नवीनीकरण स्रोतों से आता है। ■

सहकारिता से जुड़ेगी देश की 40 प्रतिशत आबादी

सहकार जागरण टीम

- **केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के सहकारिता मंत्रियों के साथ गांधीनगर में की मंथन बैठक**
- **2047 में भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने में सहकारिता की भूमिका को है बढ़ाना**
- **सहकारिता मंत्री ने राज्यों से अन्न भंडारण, सर्कुलरिटी और सहकारिता में सहकार पर बल देने का किया आह्वान**

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह सहकारिता को विकसित भारत का आधार बनाने के लिए लगातार प्रयासरत हैं क्योंकि वह जानते और मानते हैं कि भारत के हर परिवार, हर व्यक्ति को सम्मान के साथ जीने का माध्यम सिर्फ और सिर्फ सहकारिता ही बन सकती है। इसीलिए देश की 40 प्रतिशत आबादी को सहकारिता से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। भारत टैक्सी की तर्ज पर केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय ने जल्दी ही कारपेंटर्स, प्लंबर और इलेक्ट्रीशियन जैसे दिहाड़ी मजदूरों के लिए नई कोऑपरेटिव बनाने का फैसला किया है। टैक्सी चालकों की सहकारी समिति का प्रयोग बहुत सफल होता दिख रहा है, जिसे अगले तीन वर्षों में प्रत्येक म्युनिसिपल कारपोरेशन वाले शहरों तक इसकी पहुंच हो जाएगी। श्री शाह ने सहकारिता मंत्रालय की मंथन बैठक में सरकार के रोडमैप का विस्तृत ब्यौरा देते हुए सहकारिता के दायरे को व्यापक बनाने

अन्न भंडारण में बढ़े सहकारिता की हिस्सेदारी

मंथन बैठक में केंद्रीय सहकारिता मंत्री ने सहकारिता की स्वीकृति को बढ़ाने वाली बातों पर जोर दिया। इनमें अन्न भंडारण की व्यवस्था पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में देश की अन्न भंडारण क्षमता को लगभग तीन गुना बढ़ाने की जरूरत है। इसमें से दोगुना सहकारिता क्षेत्र को करनी चाहिए। इसे केवल पैक्स पर नहीं छोड़ा जा सकता है। ये सभी की जिम्मेवारी है। तहसील की कोऑपरेटिव डेयरियां, राज्य स्तरीय मार्केटिंग फेडरेशन, जिला सहकारी बैंक, जिले के खरीद-बिक्री यूनियन सबको बड़े-बड़े गोदाम बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसका एक और पहलू है कि सरकारी खरीद का 70 प्रतिशत अनाज पंजाब और हरियाणा में खरीदा जाता है। यहीं से अनाज की खरीदी होगी, यहीं भंडारण होगा और यहीं से वितरित हो जाएगा तो परिवहन की लगत में 30-40 प्रतिशत की बचत हो सकती है।

केंद्र सरकार ने सहकारिता क्षेत्र के माध्यम से विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना शुरू की है। इस योजना के तहत 7 करोड़ टन भंडारण की अतिरिक्त क्षमता विकसित की जानी है। इससे न सिर्फ अनाज की बर्बादी रूकेगी, बल्कि स्थानीय स्तर पर ही भंडारण की व्यवस्था हो जाने से परिवहन लागत में बचत के साथ-साथ अनाज वितरण में भी तेजी आएगी और ग्रामीण स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। अभी देश में अनाज भंडारण की क्षमता 14 करोड़ टन है। अन्न भंडारण योजना के तहत पहले सिर्फ पैक्स को ही गोदाम बनाने का अधिकार दिया गया था, लेकिन गोदाम निर्माण की धीमी रफ्तार को देखते हुए सरकार ने अब सभी इच्छुक सहकारी समितियों को गोदाम बनाने की छूट दे दी है।

- देश में अनाज भंडारण को तीन गुना बढ़ाने की जरूरत जिसमें से दोगुना सहकारिता क्षेत्र को करना चाहिएः श्री शाह
- सभी राज्य बंद पड़ी चीनी मिलों को शुरू करने का करें प्रयास, खस्ताहाल मिलें खाद, गैस जैसे उत्पाद बनाने की करें शुरुआत
- केंद्र सरकार की सभी योजनाओं के क्रियान्वयन में कोऑपरेटिव बैंकों की भागीदारी सुनिश्चित करने की राज्यों से अपील
- भारत टैक्सी की सर्विस तीन साल में हर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन वाले शहर तक पहुंच जाएगी

की बात कही। इस दौरान सहकारिता मंत्रालय के उठाए कदमों की गहन समीक्षा की गई।

वर्ष 2021 में सहकारिता मंत्रालय के गठन के बाद से इस क्षेत्र में व्यापक सुधार किए गए हैं। साथ ही नए-नए क्षेत्रों में सहकारिता का विस्तार करने और मजबूती देने की पहल की जा रही है। इस कड़ी में अभी हाल ही में भारत टैक्सी की शुरुआत की गई है जो सहकारिता के माध्यम से परिवहन क्षेत्र की तस्वीर और तकदीर दोनों बदलने की क्षमता रखता है। आने वाले दिनों में असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले कारपेंटर्स, प्लंबर, इलेक्ट्रीशियन आदि के लिए भी कोऑपरेटिव बनाई जाएगी। इन पहलों के माध्यम से देश की 40 प्रतिशत से अधिक आबादी को सहकारिता से जोड़ने का सरकार ने लक्ष्य रखा है।

गुजरात की राजधानी गांधीनगर में 17 फरवरी को 'सहकार से समृद्धि' के अंतर्गत सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के सहकारिता मंत्रियों के साथ श्री अमित शाह ने मंथन बैठक की। इस दौरान अपने संबोधन में उन्होंने कहा, 'प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश हर क्षेत्र में प्रगति कर रहा है।

बंद चीनी मिलों को शुरू करें राज्य सरकारें

श्री अमित शाह ने राज्यों के सहकारिता मंत्रियों से अपील की कि सभी राज्य बंद पड़ी चीनी मिलों को शुरू करने के लिए प्रयास करें। उन्होंने कहा कि जिन चीनी मिलों की आर्थिक हालत ठीक नहीं है, वह अलग से उसमें खाद बनाने, गैस बनाने आदि की प्रक्रिया शुरू करें। चीनी मिलों में अलग-अलग प्रकार के 11 उत्पाद बन सके, इसका सफल प्रयोग हो चुका है। मार्च के पहले हफ्ते में इस कार्यरचना को अंतिम रूप दिया जाएगा। जो चीनी मिलें सिर्फ चीनी बना रही है उनमें राष्ट्रीय स्तर की कोऑपरेटिव बाकी का सारा अटैचमेंट कर देगी। इसके लिए राज्यों को अपने यहां लचीली नीति बनानी पड़ेगी। केंद्रीय सहकारिता मंत्री ने सुझाव दिया कि हर राज्य अपने डेयरी और सहकारिता विभाग की टीमों को बनासकांठा डेयरी को देखने के लिए भेजें। बनासकांठा डेयरी ने कई प्रकार के काम किए हैं जिससे सभी राज्यों को काफी कुछ सीखने को मिलेगा।

आने वाले 25 साल तक विश्व के अर्थतंत्र की दिशा निर्धारित करने वाले क्षेत्र में हम आज पायोनियर के रूप में काम कर रहे हैं। इस मंथन बैठक का आयोजन इसीलिए हो रहा है कि हम 2047 में भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं। पूर्ण विकसित भारत का अर्थ है कि 140 करोड़ लोग सम्मान के साथ जी सकें, ऐसी व्यवस्था करना। भारत के हर परिवार, हर व्यक्ति को सम्मान के साथ जीने का माध्यम सिर्फ और सिर्फ सहकारिता ही बन सकती है।'

राज्यों के सहकारिता मंत्रियों से श्री अमित शाह ने आह्वान किया कि कृषि, ग्रामीण विकास और पशुपालन क्षेत्रों को जब तक हम मजबूत नही करते हैं तब तक देश का सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता है। हम सभी को मनोयोग के साथ इस प्रयास को सफल बनाने की दिशा में काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमने वैज्ञानिक तरीके से पिछले चार साल से देश के सहकारिता क्षेत्र को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है और उसके परिणाम अब दिखने लगे हैं।

सहकारिता में सहकार

'सहकारिता में सहकार' को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने सभी सहकारी समितियों को अपना बैंक खाता सहकारी बैंक में ही खोलने का निर्देश दे रखा है। अब इसे और आगे बढ़ाते हुए केंद्र सरकार की सभी योजनाओं में सहकारी बैंक को नोडल एजेंसी बनाने का फैसला किया गया है। श्री शाह ने कहा कि राज्य सरकारों को प्रयास करना चाहिए कि प्रधानमंत्री किसान कल्याण योजना, वृद्ध पेंशन जैसी योजनाओं का पैसा सहकारी बैंकों के माध्यम से ही दिया जाए। इससे सहकारी बैंकों को मजबूत बनाने में मदद मिलेगी।

दिहाड़ी मजदूरों के लिए बनेगी कोऑपरेटिव

सहकारिता को नए-नए क्षेत्रों में बढ़ाने की पहल केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय की ओर से की जा रही है। मंथन बैठक में श्री अमित शाह ने बताया कि आने वाले दिनों में खुदरा मजदूरी करने वाले लोग, जैसे कारपेंटर्स,

प्लंबर, इलेक्ट्रीशियन, जिनका शोषण होता है उनकी भी कोऑपरेटिव बनाकर उनको सम्मानजनक राशि दिलाई जाएगी। कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें संभावना तलाश कर आगे बढ़ा जा रहा है। इन कदमों से आने वाले दिनों में देश की 40 प्रतिशत से अधिक आबादी सहकारिता के साथ जुड़ जाएगी। अभी हाल ही में परिवहन क्षेत्र को सहकारिता से जोड़कर भारत टैक्सी की शुरुआत की गई है। श्री शाह के अनुसार, भारत टैक्सी आने वाले कुछ वर्षों में हर एक म्युनिशिपल कॉरपोरेशन तक पहुंच जाएगी। 3 लाख से अधिक चालक इससे जुड़े चुके हैं। इससे चालकों और यात्रियों दोनों को लाभ मिलने वाला है।

265 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन

केंद्रीय सहकारिता मंत्री ने मंथन बैठक में एथेनॉल, एनर्जी, जैविक पोटाश, वेयरहाउस व प्रोटीन पाउडर प्लांट संबंधी 265 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। साथ ही, उन्होंने प्रदर्शनी का अवलोकन और सहकारिता की बेहतर प्रथाओं एवं अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष पर रिपोर्ट का विमोचन भी किया। इस अवसर पर केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री श्री कृष्णपाल गुर्जर, श्री मुरलीधर मोहोल सहित केंद्रीय सहकारिता सचिव श्री आशीष कुमार भूटानी मौजूद थे। मंथन बैठक में विभिन्न प्रस्तुतियों के माध्यम से सहकारिता से जुड़े हुए विभिन्न विषयों पर की गई पहलों की प्रगति, उपलब्धियों और भविष्य की कार्ययोजना का उन्होंने मूल्यांकन किया। इन प्रस्तुतियों में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति देने के लिए 2 लाख नई बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों, डेयरी एवं मत्स्य सहकारी समितियों की स्थापना की प्रगति पर चर्चा हुई। इसके साथ-साथ विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना के अंतर्गत देशभर में आधुनिक गोदामों के नेटवर्क के विस्तार पर बल दिया गया जिससे किसानों को बेहतर भंडारण, मूल्य स्थिरता और बाजार तक सुगम पहुंच सुनिश्चित हो सके।

मंथन बैठक में राष्ट्रीय स्तर की तीन नई सहकारी संस्थाओं नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट लिमिटेड (एनसीईएल), नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक लिमिटेड (एनसीओएल) और भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड (बीबीएसएल) में राज्यों की सक्रिय भागीदारी और निर्यात, जैविक खेती और गुणवत्तापूर्ण बीज आपूर्ति के क्षेत्र में सहकारिता को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। इसके साथ ही राज्यों के सहकारिता कानूनों में समय के अनुसार सुधार, 97वें संविधान संशोधन के अनुसार मॉडल बायलॉज को अपनाने, सहकारी गन्ना मिलों की आर्थिक व्यवहार्यता तथा लाभ बढ़ाने, डेयरी क्षेत्र में सर्कुलरिटी एवं सस्टेनेबिलिटी को प्रोत्साहन देने तथा अमूल और एनडीडीबी के सहयोग से नई डेयरी सहकारी समितियों के गठन जैसे विषयों पर भी चर्चा की गई।

इस बैठक में दलहन एवं मक्का उत्पादन को बढ़ावा देने, सहकारी बैंकों से जुड़ी चुनौतियों के समाधान, साझा सेवा इकाई एवं अंब्रेला संगठन को मजबूत करने, सदस्यता विस्तार एवं जागरूकता अभियान को मजबूत बनाने और प्रभावी मीडिया संचार रणनीति विकसित करने जैसे विषयों पर भी विस्तार से प्रस्तुति एवं चर्चा की गई। इसके अतिरिक्त पैक्स एवं आरसीएस कार्यालयों के कंप्यूटरीकरण, राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस के उपयोग, मानव संसाधन विकास, प्रशिक्षण और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन पर भी राज्यों से अपेक्षाओं को साझा किया गया।■

ओडिशा में 3770 करोड़ रुपए की परियोजनाएं हुईं पूर्ण

राज्य के साथ मिलकर हर गांव की कोऑपरेटिव को मजबूत करेंगे: श्री अमित शाह

सहकार जागरण टीम

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार पूरे देश की समृद्धि के लिए अहर्निश प्रयास कर रही है। किसानों के हितों की सुरक्षा और कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भरता सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सरकार ने विकास के नए आयाम गढ़े हैं और सबका विकास सुनिश्चित करने के लिए योजनाओं का लाभ सभी नागरिकों तक पहुंचाने का प्रयास किया है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने इन विचारों को ओडिशा में 3770 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास योजनाओं के लोकार्पण व शुभारंभ के दौरान व्यक्त किया। एक मजबूत और अधिक समृद्ध ओडिशा के निर्माण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता के अनुरूप राज्य के विकास कार्यों को गति देते हुए श्री शाह ने कहा कि राज्य की 173 योजनाओं में से 1230 करोड़ रुपए की लागत वाली 61 योजनाएं पूरी हो गई हैं और 2116 करोड़ रुपए की लागत वाली 112 योजनाओं की शुरुआत की गई है। डेयरी, शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन और न्याय संहिता पर ट्रेनिंग से जुड़े ये प्रोजेक्ट राज्य में लोगों की भलाई को बढ़ावा देंगे, युवाओं को रोजगार प्रदान करेंगे, किसानों की समृद्धि को नई रफ्तार देंगे और महिलाओं के सशक्तीकरण के आधार बनेंगे।

श्री शाह ने कहा कि ओडिशा बहुत ज्यादा संभावनाओं वाला राज्य है और इसके पास बड़े तटीय इलाके, बहुत सारी खनिज संपदा और मेहनती आबादी है। सरकार जल्द ही ओडिशा को विकसित राज्यों की सूची में शामिल कराएगी। राज्य में डेयरी की प्रचुर संभावनाएं हैं। आगामी दिनों में यहां डेयरियों के गठन के लिए एक विशेष अभियान के रूप में

- **भुवनेश्वर में नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड (एनडीडीबी) और ओडिशा राज्य सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ (ओमफेड) के विकास कार्यों का उद्घाटन**
- **पारादीप में इफको के सल्फ्यूरिक एसिड संयंत्र-III का लोकार्पण उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में बहुत अहम सिद्ध होगा**

भारत सरकार और राज्य मिलकर ओडिशा के ग्रामीण जनजीवन को समृद्ध करने के संयुक्त प्रयास के तहत कोऑपरेटिव क्षेत्र के माध्यम से ओडिशा के गरीब किसानों, ग्रामीण जनजीवन और विशेषकर माताओं-बहनों को आत्मनिर्भर बनाने का काम करेंगे। सुभद्रा योजना के तहत राज्य में एक करोड़ माताओं-बहनों को फायदा पहुंचाया गया है। यहां सहकारिता मंत्रालय के सहयोग से सहकारी क्षेत्र के कार्यक्रमों के तहत इंडियन पोटाश लिमिटेड की बंद चीनी मिल को फिर से शुरू करने के लिए कार्य पूर्ण किया है। सरकार ने बहुत कम समय में 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से चावल खरीदने का अपना वादा पूरा किया है।

गुजरात की तरह ओडिशा के हर गांव में होगी सहकारी डेयरी

ओडिशा के विकास के संकल्प को दोहराते हुए उन्होंने कहा कि सरकार गुजरात की तरह ही ओडिशा के हर गांव में डेयरी को पहुंचाने का कार्यक्रम शुरू करेगी। साथ ही, मत्स्य पालन क्षेत्र को भी सहकारी ताकत देकर इसमें बढ़ोत्तरी की जाएगी, जिससे समुद्री भोजन निर्यात में बेहतर अवसर बनेंगे। श्री शाह ने भुवनेश्वर में

इफको और कृभको उर्वरक उत्पादन में देश को आत्मनिर्भर बनाएंगे

पारादीप में इफको के सल्फ्यूरिक एसिड संयंत्र-III के विशाल कारखाने का लोकार्पण कर श्री अमित शाह ने कहा कि आने वाले दिनों में इफको और कृभको मिलकर पूरे देश को सल्फ्यूरिक एसिड के मामले में आत्मनिर्भर बनाएंगे। श्री शाह ने कहा कि इफको ने इस प्लांट को वर्ष 2005 में 2577 करोड़ रुपए में खरीदा था और उस वक्त इसकी क्षमता 7.5 लाख मीट्रिक टन थी, जो आज बढ़कर 22 लाख मीट्रिक टन तक पहुंच गई है। इसमें ब्लेंडेड उर्वरक का उत्पादन लगभग 15 प्रतिशत है और स्वदेशी डीएपी का उत्पादन 40 प्रतिशत है। श्री शाह ने आह्वान किया कि देश में फर्टिलाइजर बनाने वाले हर कारखाने और केमिकल उद्योग में जहां भी सल्फ्यूरिक एसिड की जरूरत हो, उसका उत्पादन इफको की पारादीप यूनिट में होना चाहिए। अब इफको नैनो यूरिया, नैनो डीएपी और धरती माता के जीर्णोद्धार, जागरूकता सृजन, पोषण और सुधार के लिए पीएम-प्रणाम योजना के माध्यम से रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग में कमी लाने का आंदोलन चला रहा है, जिससे हमारी भूमि का संरक्षण होगा। इफको इस क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी कोऑपरेटिव यूनिट बन गई है।

श्री शाह ने जोर देकर कहा कि इफको जो भी कमाती है, उसका फायदा देश के पांच करोड़ किसानों तक पहुंचता है और यही इफको की सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने कहा कि इफको का कारखाना कहीं भी हो, इसके मालिक हमारे देश के पांच करोड़ किसान हैं। इफको का 41,000 करोड़ रुपए से अधिक का टर्नओवर, 3800 करोड़ रुपए से अधिक का मुनाफा और 28,000 करोड़ रुपए से अधिक की नेटवर्थ का मालिकाना हक इन्हीं किसानों के पास है और यही कोऑपरेटिव का चमत्कार है।

राज्य में विकास के प्रति पिछली सरकारों की उदासीनता पर क्षोभ व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि ओडिशा में दो दशक से भी अधिक समय से विकास रुका हुआ था और राज्य के विकास को ठप कर दिया गया था। उस दौरान जनजातियों के कल्याण के लिए ओडिशा में कोई योजना नहीं बनी, समुद्र तट के विकास के लिए कोई योजना नहीं बनी और शहरों के विकास के लिए भी कोई प्रयास नहीं किया गया। राज्य में सहकारिता और डेयरी क्षेत्र के लिए भी राज्य में कोई ठोस कार्य नहीं हुआ। श्री शाह ने कहा कि आज ओडिशा नए भारत की उम्मीद, ओडिशा की मौलिकता और सभी अवसरों का पता लगाकर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत सरकार राज्य के साथ मिलकर यहां दो दशकों में विकास की कमी को पांच वर्षों में पूरा करेगी। लोक कल्याण के प्रति सरकार के दायित्व बोध को दोहराते हुए श्री शाह ने कहा कि लोकतंत्र में जिन्हें सत्ता प्राप्त होती है, उनका दायित्व होता है कि वे जनता की अपेक्षाओं पर खरे उतरें, उनके सुख-दुख में उनके साथ खड़े रहें और जनता की समृद्धि, शांत माहौल और राज्य के विकास के लिए प्रयत्न करें।

श्री शाह ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बन चुका है और यह गति अब रुकेगी नहीं।

नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड (एनडीडीबी) और ओडिशा राज्य सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ (ओमफेड) के विकास कार्यों का उद्घाटन भी किया। उन्होंने प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों (पैक्स) के लिए सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी) और 141 मंडियों का भी उद्घाटन किया और सहकारिता विकास संगोष्ठी के दौरान कहा कि भारत सरकार का सहकारिता मंत्रालय और ओडिशा सरकार मिलकर अमूल की तर्ज पर राज्य में डेयरी विकास को आगे बढ़ाएंगे और हर गांव में कोऑपरेटिव का एक मजबूत आधार बनाने का काम करेंगे।

इस मौके पर नयी ओडिशा सहकारी नीति-2026 की शुरुआत की गई, जिससे ओडिशा इस तरह की नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। साथ ही, विभिन्न परियोजनाओं के विकास के लिए छह समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए, जिनमें बरम्बा सहकारी चीनी मिल का पुनरुद्धार, कटक में एक आइसक्रीम संयंत्र की स्थापना और त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय में एक विद्यालय की स्थापना और राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की एक शाखा की स्थापना शामिल है।

श्री शाह ने कहा कि ओडिशा ने दशकों तक नक्सलवाद के दंश को सहन किया है और इसके परिणाम भुगते हैं। नक्सलवाद-प्रभावित सभी क्षेत्रों में विकास को पहुंचाने के लिए हम तीव्र गति से काम करने के लिए संकल्पबद्ध हैं और हर वह आदिवासी जो नक्सलवाद के कारण विकास से महरूम रह गया था, उसके विकास के लिए दोगुनी गति से काम करने के लिए हम समर्पित हैं। श्री मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार ने नक्सलवाद के खात्मे के लिए एक निर्णाणक लड़ाई शुरू की थी और 31 मार्च, 2026 तक देश नक्सलवाद से मुक्त हो जाएगा। ■

भारत टैक्सी: सारथियों की

सहकार जागरण टीम

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की 'सहकार से समृद्धि' की आकांक्षा के अनुरूप सहकारिता मंत्रालय सहकारी संस्थाओं को रोजगार सृजन, सामाजिक सुरक्षा तथा जमीनी स्तर पर आर्थिक भागीदारी के प्रभावी साधन के रूप में सशक्त बना रहा है। सहकारी क्षेत्र को सुदृढ़ करने और समावेशी, नागरिक-केंद्रित पहल के रूप में मंत्रालय ने एक अभिनव पहल करते हुए 'भारत टैक्सी' का शुभारंभ किया है, जो मोबिलिटी क्षेत्र में एक परिवर्तनकारी पहल साबित हो रही है। सहकारी-नेतृत्व वाले इस टैक्सी सेवा में चालकों को स्वामित्व, प्रबंधन और मूल्य सृजन के केंद्र में रखा गया है और उन्हें 'सारथी' कहा गया है। सहकारी क्षेत्र की इस अनूठी पहल पर भारत टैक्सी के सारथियों ने अपनी खुशी का इजहार किया। राजधानी दिल्ली के टैक्सी ड्राइवर इसे लेकर काफी उत्साहित हैं। उन्होंने सहकारिता मंत्रालय की इस पहल के लिए सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह को दिल से धन्यवाद दिया। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, नोएडा व गाजियाबाद और गुजरात के अमहदाबाद, राजकोट, सोमनाथ और द्वारका में भारत टैक्सी ने अपनी पैठ मजबूत बनानी शुरू कर दी है। इसकी सफलता को देखते हुए अगले तीन वर्षों में देश के सभी राज्यों में भारत टैक्सी का विस्तार हो जाएगा।

ड्राइवर **हरिओम** का कहना है 'हमारी आकांक्षाओं के अनुरूप ही सहकारिता क्षेत्र में भारत टैक्सी का

आगमन हुआ है। हम सभी ड्राइवर भाइयों के लिए यह सुनहरा मौका है।' इसके आने के बाद से प्राइवेट सेक्टर की टैक्सी संचालन करने वाली कंपनियों के होश उड़ गये है। जो सुविधाएं और प्रबंधन भारत टैक्सी का है उसके आसपास भी वो नहीं टिकते हैं। सारथी भाइयों को यह बहुत अच्छा प्लेटफार्म मिला है। भारत टैक्सी देश की अपनी है। सहकारिता के इस टैक्सी प्लेटफार्म से सभी को जुड़ना चाहिए। इसमें कमीशन के नाम पर लूट नहीं है। टैक्सी का जितना किराया होगा, सब ड्राइवर को ही मिलेगा। मैं दो-तीन महीने से भारत टैक्सी के तहत टैक्सी चला रहा हूं। इससे मुझे बहुत राहत मिली है। अच्छी कमाई के साथ मैं अपने परिवार की देखभाल अच्छे से करने लगा हूं। इसलिए सभी टैक्सी ड्राइवर भाइयों को इससे जुड़ना चाहिए और इसे मजबूत बनाना चाहिए। अन्य निजी कंपनियों की तरह इसमें शोषण नहीं है। ड्राइवरों की सुरक्षा का भी पूरा ख्याल रखा गया है। हम भारत टैक्सी को सफल बनाएंगे।

महिला सारथी **संतोष कुमारी** ने भारत टैक्सी प्लेटफार्म को उपयोगी बताते हुए कहा कि टैक्सी सर्विस में पहले महिला ड्राइवरों के लिए कोई अवसर नहीं था। लेकिन महिलाओं के हितों का ध्यान रखते हुए भारत टैक्सी के प्लेटफार्म ने महिला सारथियों को अच्छा अवसर उपलब्ध कराया है। शुरू में इस प्लेटफार्म से एक-दो महिलाएं ही जुड़ी थीं जो अब धीरे-धीरे इनकी संख्या बढ़ रही है। 'इससे जुड़कर मैं अच्छी कमाई कर रही हूं।

इस प्लेटफार्म पर समय की कोई बाध्यता नहीं है। मैं अपनी सुविधानुसार इससे जुड़कर कमाई करती हूं। मैं बच्चों को स्कूल छोड़कर आती हूं। बाद में उन्हें स्कूल से लेकर घर भी चली जाती हूं। उन्हें ट्यूशन के लिए भेजकर फिर से इस प्लेटफार्म से जुड़ जाती हूं। इससे जुड़कर अब मैं स्वतंत्र होकर काम कर पाती हूं और अपना इनकम बढ़ाने में सक्षम हो पाई हूं। भारत टैक्सी का अनुभव मेरे लिए शुभचिंतक परिवार की तरह का हो गया है।'

हमारी कुछ सहेलियां भी ड्राइविंग सीख रही हैं जो जल्दी ही भारत टैक्सी से जुड़ेंगी। सहकारिता के इस प्रयास से महिला ड्राइवरों और महिला यात्रियों को बहुत सहूलियत होगी। भारत टैक्सी में महिलाओं के लिए यह व्यवस्था की गई है कि अगर कोई महिला हमारी टैक्सी बुक करेगी तो उसे महिला सारथी की सुविधा मिलेगी। महिला सुरक्षा के लिए सरकार की इस बड़ी पहल की जितनी तारीफ की जाए, वह कम है। इसके लिए हम सहकारिता मंत्रालय और सरकार के बहुत आभारी हैं।

कहानी, उन्हीं की जुबानी

भारत टैक्सी से अपनी सारथी यात्रा की शुरुआत करने वाली **पूनम** का कहना है 'मैं हाउस वाइफ हूं। बचपन से मेरा शौक ड्राइविंग का था, लेकिन मैं ड्राइविंग नहीं सीख पाई। मुझे भारत टैक्सी के बारे में पता चला तो मुझे लगा कि मैं घर में रहकर क्यां करूंगी, मौका मिला है

तो बाहर निकली और अपने बचपन की इच्छा को पूरी कर रही हूं। इसीलिए मैं महिला सारथी बनकर आ गई। भारत टैक्सी में ड्राइविंग करके दूसरों को भी इसमे भाग लेने के लिए प्रेरित कर रही हूँ। भारत टैक्सी के प्लेटफार्म पर महिलाओं के लिए बहुत अवसर है। इसलिए मैं उनसे अपील करती हूं कि वो घर से बाहर निकलें और भारत टैक्सी से जुड़कर काम करें और अपनी इच्छाओं-आकांक्षाओं को पूरा करें।' इससे मेरा आत्मविश्वास मजबूत हुआ है। मैं भारत टैक्सी एक माह से चला रही हूं। इससे जुड़कर अच्छी कमाई हो रही है। मैं इससे संतुष्ट हूं। क्योंकि इस प्लेटफार्म पर किसी को कोई कमीशन नहीं देना पड़ता है। जो भी किराया होता है, सब ड्राइवर को ही मिलता है। भारत टैक्सी की सेवा लेने वाले यात्री भी इससे पूर्ण संतुष्ट हैं। मैं सभी से इससे जुड़ने की अपील करती हूं। क्योंकि इससे जुड़कर जहां ड्राइवरों के जीवन में बदलाव दिखने लगा है। कमाई बढ़ रही है। भारत टैक्सी प्लेटफार्म की सेवाओं से यात्री भी संतुष्ट हैं। भारत टैक्सी के अनुभव से मैं कह सकती हूं कि टैक्सी चालकों को इससे जुड़कर अपना हित साधना चाहिए।

सारथी **विनोद कुमार शाह** ने भारत टैक्सी को धन्यवाद देते हुए कहा 'इससे जुड़कर काम अच्छा चल रहा है। इससे अच्छी कमाई भी हो रही है। कंपनी की ओर से बहुत बढ़िया सर्विस दी जा रही है। ड्राइवरों को हर तरीके से सहयोग मिल रहा । कंपनी की सेवाओं से यात्री भी खुश और संतुष्ट हैं। यह दूसरी निजी कंपनियों से अच्छी सेवा दे रही है। इसके कारण टैक्सी ड्राइवर और यात्री दोनों खुश हैं। सभी लोगों को इससे जुड़कर इसका लाभ उठाना चाहिए। सहकारिता की भारत टैक्सी में ड्राइवर भाइयों की सुरक्षा का पूरा ख्याल रखा जाता है।' सरकार की इस व्यवस्था के लिए हम सहकारिता मंत्रालय को दिल से धन्यवाद देते हैं।

भारत टैक्सी से जुड़े सारथी **संतोष कुमार** ने बताया कि अभी तक घरेलू बाजार में दो तीन निजी कंपनियां ही टैक्सी सेवा देती रही हैं, लेकिन उनके प्लेटफार्म से जुड़कर टैक्सी ड्राइवरों को लाभ नहीं हो रहा था। इससे परेशान

होकर कई ड्राइवरों ने तो अपनी टैक्सी ही बेच दी। इस काम को ही बंद कर दिया। वे कोई दूसरा काम करने लगे। क्योंकि टैक्सी चलाने में काफी खर्च आता था। हर महीने पासिंग, टैक्स, मेंटीनेंस, एसी आदि पर काफी व्यय होता था। इसके मुकाबले बचत बहुत कम होती थी। लेकिन भारत टैक्सी के आने से अब उम्मीद जगी है। 'मैं इससे जुड़कर खुद को भाग्यशाली समझता हूं । टैक्सी ड्राइवरों को सारथी नाम देकर भारत टैक्सी ने उन्हें सम्मान दिया है। ड्राइवरों से अपील करता हूं कि वे भारत टैक्सी से जुड़ें और दूसरों को भी इससे जुड़ने के लिए प्रेरित करें। इसे मजबूत बनाएं और खुद भी सशक्त बनें। भारत टैक्सी ड्राइवरों का पूरा ध्यान रखती है।'

सारथी **सुदेश** ने बताया कि भारत टैक्सी की शुरुआत ने टैक्सी सेवा से जुड़े टैक्सी ड्राइवरों के जीवन में एक नई उम्मीद

जगाई है। कोऑपरेटिव से जुड़कर हजारों ड्राइवरों को बड़ी राहत मिली है। यहां हमारा कोई आर्थिक नुकसान नहीं हो रहा है और हम अपनी मेहनत के लाभ के हकदार हो गए हैं। केवल 500 रुपए जमा करके ड्राइवर भारत टैक्सी परिवार का सदस्य बन रहे हैं। अब इस सहकारी संस्था का जितना विकास होगा, उसके अनुसार कुल लाभ में भी उनकी भागीदारी होगी। हमारी टैक्सी बुक करने में ग्राहकों को भी व्यस्त टाइम में जो अधिक किराया देना पड़ता था, उससे यहां छुटकारा मिल गया है।■

छत्तीसगढ़ के रायपुर में एक राष्ट्रीय कॉन्क्लेव

बस्तर देश का सबसे समृद्ध आदिवासी संभाग बनेगा

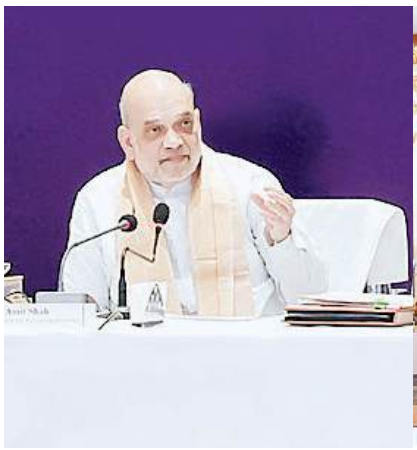

सहकार जागरण टीम

- **प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में भारत के सफल होने से ही संपूर्ण विश्व स्थिर और समृद्ध होगा**
- **छत्तीसगढ़ को लाल आतंक से मुक्त करेंगे और देखते ही देखते इसे देश का नंबर एक राज्य बनाएंगे**

छत्तीसगढ़ 25 वर्षों का हो गया है और इन वर्षों में राज्य में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। पहले यह बीमारू और नक्सलवाद से ग्रस्त राज्य माना जाता था, लेकिन आज यह बीमारू राज्य से बाहर निकल कर विकसित राज्य बनने की कगार पर है। यहां नक्सलवाद का नामोनिशान समाप्त होने वाला है। राज्य के इस गुणात्मक परिवर्तन का उल्लेख केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के रायपुर में एक राष्ट्रीय कॉन्क्लेव के दौरान किया।

साप्ताहिक पत्र 'ऑर्गेनाइजर' के 'भारत प्रकाशन' द्वारा प्रकाशित पुस्तक 'छत्तीसगढ़ @ 25 : शिफ्टिंग द लेंस' पर चर्चा के दौरान श्री शाह ने कहा कि छत्तीसगढ़ आज लगभग साढ़े सात प्रतिशत विकास दर के साथ आगे बढ़ रहा है जो अकल्पनीय है। उन्होंने कहा कि देशभर की सरकारों में अगर किसी राज्य सरकार ने आदिवासी कल्याण के लिए सबसे अच्छा काम किया है तो वह छत्तीसगढ़ सरकार ही है।

श्री शाह ने कहा कि अगर बस्तर माओवादी हिंसा से पीड़ित न होता, तो अपार खनिज संपदा से परिपूर्ण यह संभाग देश का सबसे समृद्ध क्षेत्र होता। उन्होंने विश्वास के साथ कहा कि 10 साल बाद बस्तर देश का सबसे विकसित आदिवासी ज़िला होगा। यहां 90 प्रतिशत क्षेत्र नक्सलवाद से मुक्त हो चुका है और 31 मार्च से पहले ही हम पूरे देश से माओवादी समस्या को जड़ समेत उखाड़ कर फेंक देंगे। उन्होंने कहा कि किसी समस्या का समाधान बंदूक से निकलता है, यह माओवादी विचारधारा की ही उपज है, जबकि हमारे संविधान की आत्मा संवाद, चर्चा और समाधान में है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा, समृद्धि और स्थिरता शब्द किसी भी राष्ट्र या राज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं और छत्तीसगढ़ जैसे राज्य के लिए तो और भी अधिक महत्वपूर्ण है। श्री शाह ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री बने, तब उन्होंने निर्णय किया कि छोटे राज्यों का प्रयोग सिर्फ प्रयोग मात्र नहीं है बल्कि वहां की जनता की आकांक्षाओं की पूर्ति है। उनके समय में ही एक साथ झारखंड, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ के निर्माण का निर्णय किया गया।

विकास की राह पर आगे बढ़ रहा प्रदेश

राज्य में नए सिरे से हो रहे विकास कार्यों का जिक्र करते हुए श्री शाह ने कहा कि अब यहां फिर से स्कूल, अस्पताल और सड़क बन गए हैं और क्षेत्र को रेल यातायात से जोड़ा जा रहा है। राज्य ने कृषि क्षेत्र में 17 प्रतिशत, उद्योग क्षेत्र में 48 प्रतिशत और सेवा क्षेत्र में 35 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की है। ग्रामीण सड़क निर्माण में 98 गुना वृद्धि और निवेश में 247 गुना वृद्धि दर्ज हुई है। भारत सरकार ने यहां सात लाख हेक्टेयर कृषि क्षेत्र को सिंचित करने की योजना को भी मंजूरी दे रही है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2000 और 2025 के छत्तीसगढ़ के बजट की तुलना करें तो राज्य के बजट में 30 गुना वृद्धि हुई है। राज्य की प्रति व्यक्ति आय में 17 गुना वृद्धि हुई है और

छत्तीसगढ़ में विकास कार्यों की समीक्षा कर बोले श्री शाह

पीढ़ियों को अंधकार में धकेलने वाले नक्सलवाद से निजात मिलेगी

सहकार जागरण टीम

- केंद्र और राज्य की सुरक्षा केंद्रित रणनीति, इंफ्रास्ट्रक्चर, नक्सल फाइनेंशियल नेटवर्क पर प्रहार व आत्म समर्पण नीति से आया सकारात्मक बदलाव

केंद्र और छत्तीसगढ़ सरकार की सुरक्षा केंद्रित रणनीति, इंफ्रास्ट्रक्चर, नक्सल फाइनेंशियल नेटवर्क पर प्रहार व आत्मसमर्पण नीति के सकारात्मक परिणाम आए हैं। कई पीढ़ियों को गरीबी और अशिक्षा के अंधकार में धकेलने वाले नक्सलवाद से देश जल्द ही निजात पाने वाला है। यह अंत के कगार पर पहुंच चुका है और 31 मार्च से पहले देश पूरी तरह नक्सल-मुक्त हो जाएगा। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने इन तथ्यों को छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में विभिन्न विकास कार्यों और वामपंथी उग्रवाद पर सुरक्षा समीक्षा बैठक के दौरान व्यक्त किया।

श्री शाह ने कहा कि छत्तीसगढ़ कभी नक्सली हिंसा का गढ़ था, लेकिन प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में चल रही डबल इंजन सरकार में यह अब विकास का पर्याय बन चुका है। यहां के युवा खेल, फॉरेंसिक और तकनीकी शिक्षा को गति देते हुए अपनी संस्कृति व परंपराओं को भी सहेज रहे हैं। इस राज्य ने सुरक्षा और विकास दोनों मोर्चों पर उल्लेखनीय प्रगति की है। श्री शाह ने कहा कि यह सुनिश्चित करने पर जोर दिया कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के लोगों को विकास के समान अवसर प्राप्त हों। वहीं, माओवादियों के खिलाफ चल रही लड़ाई में विभिन्न राज्यों और केंद्रीय एजेंसियों के बीच सुचारू समन्वय की जरूरत पर जोर देते हुए श्री शाह ने कहा कि यह लड़ाई बिखरी हुई नहीं होनी चाहिए और न ही शेष बचे माओवादियों को अन्य राज्यों में भागने का कोई मौका मिलना चाहिए।■

राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) में 25 गुना वृद्धि हुई है। पिछले 25 वर्षों में सिंचाई के क्षेत्र में दो गुना वृद्धि, खरीफ फसलों के उत्पादन में तीन गुना और रबी फसलों में लगभग छह गुना वृद्धि हुई है। यहां पहले केवल सात ज़िला अस्पताल थे जो 30 हो गए हैं और एक की जगह अब 16 मेडिकल कॉलेज हो गए हैं। श्री शाह ने कहा कि पहले कुपोषण से होने वाली मृत्यु दर 61 थी जो अब घटकर 15 हो गई है, मातृमृत्यु दर प्रति लाख 365 थी जो सरकार के प्रयासों से 146 हो गई है और शिशु मृत्यु दर भी 79 से घटकर 37 हो गई है। यहां साक्षरता दर 65 प्रतिशत से बढ़कर 79 प्रतिशत हो गई है। राज्य में पहले जहां कोई आवासीय एकलव्य विद्यालय नहीं था, वहां 75 एकलव्य विद्यालय संचालित हो रहे हैं।

भारत सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार किसी पर गोली चलाना नहीं चाहती, सभी नक्सली हथियार डाल दें, तो सरकार रेड कारपेट बिछाकर उनका स्वागत करेगी। श्री शाह ने अपील किया कि जो बच्चियां हाथ में बंदूक लेकर खड़ी हैं, वे जरूर सरेंडर करें, क्योंकि आगे बहुत अच्छा जीवन उनकी राह देख रहा है। उन्होंने अफसोस जाहिर किया कि माओवादियों की हिंसा में हजारों आदिवासी बच्चे मारे गए और उनके जीवन बर्बाद हो गए। श्री शाह ने स्पष्ट कहा कि किसी समस्या को विकास में अनदेखी की उपज मानने वाले माओवादी देश को गुमराह कर रहे हैं, क्योंकि जब नक्सली समस्या शुरू हुई, हमारे देश में उस समय 100 ज़िले बस्तर से अधिक अविकसित थे, लेकिन वहां नक्सलवाद की समस्या नहीं पनपी। श्री शाह ने कहा कि यह समस्या कानून व्यवस्था और विकास के साथ नहीं जुड़ी है, बल्कि 'आइडियोलॉजी' के साथ जुड़ी है। माओवादियों ने इस क्षेत्र के विकास को रौंदा है। इसका कारण यह है कि माओवादी विचारधारा में समस्या का समाधान बंदूक से ही निकलता है। श्री शाह ने कहा कि माओवादियों ने गरीब, अशिक्षित, आदिवासी युवा बच्चों के हाथों में हथियार पकड़ा दिया और तिरुपति से पशुपतिनाथ का रेड कॉरिडोर का नारा देकर लाल आतंक का समर्थन किया और दशकों तक इस क्षेत्र में विकास को नहीं पहुंचने दिया।■

केरलम को विकास परियोजनाओं की सौगात देकर बोले प्रधानमंत्री श्री मोदी

केरलम के लोगों के जीवन को सुगम बनाएंगी विकास परियोजनाएं

सहकार जागरण टीम

इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश किया गया प्रत्येक रुपया युवाओं के लिए व्यापक रोजगार सृजन में उत्प्रेरक का काम करता है। ये बहुक्षेत्रीय परियोजनाएं राज्य के समृद्ध भविष्य के लिए आवश्यक आधारशिला हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये परियोजनाएं 'विकसित केरलम' के हमारे संकल्प को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने केरलम के तटीय शहर कोच्चि में 11 हजार करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करते हुए यह विचार व्यक्त किया।

कोच्चि रिफाइनरी में पॉलीप्रोपाइलीन यूनिट की आधारशिला रखने का उद्देश्य पेट्रोलियम क्षेत्र को मजबूत बनाने को बताते हुए श्री मोदी ने कहा कि इस यूनिट से प्रति वर्ष चार लाख टन पॉलीप्रोपाइलीन का उत्पादन होने की उम्मीद है। इससे पैकेजिंग, कपड़ा और चिकित्सा उपकरण उद्योगों को सहयोग मिलेगा। आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए, 'मेक इन इंडिया' के लिए पेट्रोलियम सेक्टर का विस्तार बहुत आवश्यक है। भारत को वैश्विक विनिर्माण और प्रौद्योगिकी केंद्र के रूप में मजबूत करने के उद्देश्य से कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) और सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में देश की प्रगति को सतत ऊर्जा की बढ़ती मांग से जोड़ते हुए श्री मोदी ने कहा कि केरलम को सौर ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में प्रगति सुनिश्चित करने के लिए पश्चिम कल्लाडा में 50 मेगावाट की फ्लोटिंग सोलर परियोजना की आधारशिला रखी गई है। केरलम में बड़ी संख्या में जलाशय मौजूद हैं, इसलिए यहां फ्लोटिंग सोलर पावर के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। हमारा प्रयास है कि केरलम सौर ऊर्जा उत्पादन में और आगे बढ़े। इससे पर्यावरण संरक्षण में भी मदद मिलेगी और प्रदूषण से छुटकारा मिलेगा। बिजली का उत्पादन बढ़ने से राज्य में उद्योग-धंधों का विकास होगा और अन्य कारोबार को भी फलने-फूलने का अवसर हासिल होगा।

- **मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के लिए पेट्रोलियम क्षेत्र का विकास जरूरी**
- **विकसित केरलम के संकल्प को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी परियोजनाएं**

अमृत भारत स्टेशन योजना और रेलवे विद्युतीकरण के माध्यम से क्षेत्रीय संपर्क में हुई प्रगति का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भी शोरानूर जंक्शन, कुट्टीपुरम और चांगनास्सेरी में आधुनिकीकरण के प्रयासों के साथ-साथ नई पलक्कड़-पोल्लाची ट्रेन सेवा से केरलम और तमिलनाडु दोनों राज्यों के निवासियों के यात्रा अनुभव में बड़ा बदलाव आने वाला है। अब उन्हें आवागमन का सस्ता साधन सुलभ हो सकेगा। सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर के विषय पर श्री मोदी ने कहा कि कोझिकोड बाईपास और अझिक्कल बंदरगाह से बेहतर कनेक्टिविटी सहित नई छह-लेन परियोजनाएं यात्रा में लगने वाले समय और भीड़भाड़ को काफी हद तक कम कर देंगी। अब लोग कम समय में अपने गंतव्य तक पहुंच सकेंगे और ईंधन की भी बचत होगी। इससे लोगों को आर्थिक लाभ होगा।■

राजधानी दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने जताया संकल्प

खोए सामर्थ्य को वापस पाने को भारत प्रतिबद्ध

सहकार जागरण टीम

- पिछले 11 वर्षों में देश की चेतना में एक नई ऊर्जा का प्रवाह हुआ है
- बड़े विजन, धैर्य व समय पर लिए गए निर्णयों से होता है राष्ट्र निर्माण

हमारे शास्त्र कहते हैं– 'तत् त्वम् असि', अर्थात् जिस ब्रह्म की खोज में हम निकले हैं, वो हम ही हैं, वो हमारे भीतर ही है। जो सामर्थ्य हमारे भीतर है उसे हमें पहचानना है। पिछले 11 वर्षों में भारत ने अपने उसी सामर्थ्य पहचाना है, उसे सशक्त करने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है और उस खोए हुए सामर्थ्य को पाने को प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में यह विचार व्यक्त किया। किसी देश में निहित सामर्थ्य को पीढ़ियों में सृजित होने की बात कहते हुए श्री मोदी ने कहा कि पिछले 11 वर्षों में भारत अपने खोए हुए सामर्थ्य को वापस पाने का प्रयास कर रहा है। इसके परिणामस्वरूप राष्ट्रीय चेतना में नई ऊर्जा का प्रवाह हुआ है।

उन्होंने कहा कि देश अब विनिर्माण पर नए सिरे से ध्यान, उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार और आर्थिक नीतियों को सुदृढ़ करने पर केंद्रित है, ताकि एक मजबूत आधार तैयार किया जा सके। बैंकिंग प्रणाली को सशक्त बनाकर और दोहरे अंकों की महंगाई पर सफलतापूर्वक नियंत्रण स्थापित करके सरकार ने भारत को प्रभावी रूप से दुनिया के विकास इंजन में बदल दिया है।

डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत के नेतृत्व और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) की सफलता का हवाला देते हुए श्री मोदी ने बताया कि इसके माध्यम से 24 लाख करोड़ रुपए की राशि बिना किसी लीकेज के सीधे लाभार्थियों तक पहुंचाई गई है। देश उस दौर से आगे बढ़ गया है, जब तीन करोड़ परिवारों के पास बिजली नहीं थी। सौर ऊर्जा के मामले में भारत दुनिया के शीर्ष देशों में शामिल हो चुका है। वंदे भारत और नमो भारत के युग में भारत की रेल आधारित शहरी परिवहन प्रणाली विकसित होकर विश्व का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क बन गया है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) विषय पर प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछली औद्योगिक क्रांतियों में भारत और ग्लोबल साउथ सिर्फ अनुयायी थे। लेकिन कृत्रिम बुद्धिमत्ता के युग में भारत निर्णयों में सहभागी है और उन्हें आकार दे रहा है। आज हमारे पास अपना एआई स्टार्टअप इकोसिस्टम है और हम एआई डेटा प्रोसेसिंग के लिए आवश्यक पावर के लिए तेजी से काम कर रहे हैं।

आत्मनिर्भरता की चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हम सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का निर्माण कर रहे हैं और ग्रीन हाइड्रोजन, सौर ऊर्जा तथा इथेनॉल मिश्रण को प्राथमिकता दे रहे हैं। साथ ही रक्षा उत्पादन, मोबाइल विनिर्माण, ड्रोन प्रौद्योगिकी और महत्वपूर्ण खनिज अवसंरचना में निवेश कर रहे हैं। व्यापक विजन, धैर्य और समय पर लिए गए निर्णयों से राष्ट्र-निर्माण होता है।■

असम के नाथनपुर गांव से वाइब्रेंट विलेजेज प्रोग्राम-II की शुरुआत

हर सीमांत गांव भारत का प्रथम गांव है: श्री अमित शाह

सहकार जागरण टीम

- **आने वाले दिनों में असम देश के विकसित राज्यों की श्रेणी में शामिल हो जाएगा, जिसमें वायब्रेंट विलेजेज-2 कार्यक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका होगी**
- **पहल का मुख्य फोकस 2047 तक विकसित भारत विजन के अनुसार सुरक्षित, मजबूत और समृद्ध सीमावर्ती समुदाय को प्रोत्साहन पर है**

'हर सीमांत गांव देश के अन्य गांवों जितना विकसित हो, सीमा से पलायन न हो और सीमा से घुसपैठिए न घुस सकें। सुरक्षित असम के माध्यम से सुरक्षित भारत की कल्पना हमारी सरकार का संकल्प है।' केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने इन संकल्पों को असम के नाथनपुर गांव में वाइब्रेंट विलेजेज प्रोग्राम-2 की शुरुआत के मौके पर व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने इस कार्यक्रम के माध्यम से पूरी बराक घाटी और असम के सीमांत ज़िलों के सभी गांवों में भारत के अन्य गांवों जितनी सुविधाएं देने की शुरुआत की है। श्री शाह ने कहा कि करीब 7,000 करोड़ रुपए की लागत से वायब्रेंट विलेजेज-2 कार्यक्रम के जरिए देश के 15 राज्यों और दो केंद्रशासित प्रदेशों के अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे 334 ब्लॉक में लगभग 2000 सीमांत गांवों का विकास होगा, जिसमें सुरक्षा, योजना संतृप्ति और कनेक्टिविटी से जुड़ी कई योजनाएं शामिल हैं। इनमें नौ ज़िले, 26 ब्लॉक और 140 गांव असम के हैं और इन गांवों में भी देश के अन्य गांवों के समान ही सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगीं। इस कार्यक्रम में अरूणाचल प्रदेश, बिहार, गुजरात, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के गांव भी शामिल हैं।

श्री शाह ने कहा कि वायब्रेंट विलेजेज-1 कार्यक्रम में सरकार ने तय किया कि सीमा पर स्थित हर गांव आखिरी नहीं, बल्कि भारत का प्रथम गांव है। अब असम के गांव भी देश के प्रथम गांव बनेंगे, जो सिर्फ विकास की दौड़ में ही नहीं, बल्कि रोजगार, शिक्षा, सड़क और दूरसंचार के क्षेत्र में भी

सुरक्षित, मजबूत और समृद्ध सीमावर्ती समुदाय

सीमांत गांवों को मजबूत बनाने और सीमावर्ती क्षेत्रों में सर्वांगीण विकास को बढ़ावा देने की दिशा में वायब्रेंट विलेजेज-2 कार्यक्रम एक महत्वपूर्ण योजना है। इस पहल का फोकस 2047 तक विकसित भारत के विजन के अनुसार सुरक्षित, मजबूत और समृद्ध सीमावर्ती समुदाय को प्रोत्साहन देना है। इसमें सीमांत गांवों में जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने, आधारभूत सेवाओं तक पहुंच बढ़ाने और रोजगार के सतत अवसर निर्मित करने पर बल दिया गया है। इन गांवों को मजबूत करने के साथ-साथ यह प्रोग्राम सीमांत क्षेत्रों के स्थानीय निवासियों को देश की आंख और कान बनने में भी मदद करेगा और इससे सीमा सुरक्षा, सीमापार अपराधों को रोकने और आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने में निर्णायक मदद मिलेगी।

देश के प्रथम गांव होंगे। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में असम देश के विकसित राज्यों की श्रेणी में शामिल हो जाएगा और इसमें वायब्रेंट विलेज-2 कार्यक्रम की बेहद अहम भूमिका होगी।

पिछले पांच वर्षों में असम में प्रतिदिन 14 किमी सड़क निर्माण

श्री शाह ने कहा कि एक जमाना था जब सीमांत गांव को देश का आखिरी गांव कहा जाता था क्योंकि वह विकास, रोजगार, बिजली कनेक्टिविटी और शिक्षा की दृष्टि से पिछड़ा हुआ था। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने राज्य के विकास के लिए कोई उल्लेखनीय कार्य नहीं किया। वहीं, प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार व राज्यों ने वह कर दिखाया जो पिछली सरकारें 50 वर्षों में भी नहीं कर सकीं। उन्होंने कहा कि पिछले पांच वर्षों में असम में प्रतिदिन 14 किलोमीटर सड़क निर्माण कार्य हुआ है, जो देश में सबसे अधिक है। राज्य में 24 हजार किलोमीटर से अधिक सड़कों को अपग्रेड किया गया है, अनेक पुल बनाए गए हैं। श्री शाह ने कहा कि हमारी डबल इंजन की सरकार ने चार बड़े नए पुल पिछले 10 वर्षों में असम की जनता को दिए हैं। सरकार ने राज्य में व्याप्त 37 प्रतिशत बहुआयामी गरीबी को वर्ष 2023 तक घटाकर 14 प्रतिशत कर दिया है। सरकार के समग्र विकास के प्रयासों से वर्ष 2013-14 में असम की प्रति व्यक्ति आय 49 हजार रुपए वर्ष 2024-25 में तीन गुना बढ़कर एक लाख 54 हजार रुपए हो गई। जनता के मन में आत्मविश्वास बढ़ा है और यह राज्य में सुशासन और शांति के कारण संभव हुआ है। उन्होंने कहा कि राज्य की हिमंता बिस्वा सरमा सरकार ने पहले होने वाले यहां बम धमाकों और उग्रवाद को भी समाप्त किया है।

श्री शाह ने कहा कि आज असम पूर्वोत्तर राज्यों का हेल्थ हब बन गया है। राज्य में 27 हजार करोड़ रुपए का सेमीकंडक्टर प्लांट आया है। भारत सरकार ने राज्य में सड़कों के विकास के लिए 30 हजार करोड़ रुपए, रेलवे के लिए 95 हजार करोड़ रुपए और एयरपोर्ट के लिए 10 हजार करोड़ रुपए दिया है। उन्होंने कहा कि हम असम के विकास के लिए एक आकर्षक औद्योगिक पॉलिसी भी लेकर आए हैं।■

'हिंद दी चादर' श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहादत समागम में बोले प्रधानमंत्री श्री मोदी

सिख आस्था के सम्मान के साथ ही प्रगति के नए अवसर सृजित कर रही सरकार

सहकार जागरण टीम

भारत का इतिहास शौर्य, समन्वय और सहयोग का इतिहास है। 'सिख समुदाय की आस्था का सम्मान करना और उनकी प्रगति के लिए नए अवसर सृजित करना सरकार का दायित्व और सेवा का विशेषाधिकार दोनों है।' प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने इन विचारों को 'हिंद दी चादर' श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी के 350वें शहादत पर्व पर उनका पुण्य स्मरण कर वीडियो कांफ्रेंस के जरिए नवी मुंबई में शहीदी समागम को संबोधित करते हुए व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि हम सभी इस महत्वपूर्ण जयंती पर महान गुरु को याद कर रहे हैं। ऐसे ऐतिहासिक तथा पवित्र आयोजन का हिस्सा बनना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। श्री मोदी ने जोर देते हुए कहा, 'समागम का उद्देश्य केवल इतिहास को याद रखना नहीं, बल्कि उसे अपने आचरण में आत्मसात करना है।' उन्होंने कहा कि जिस युग में गुरुओं ने बलिदान की पराकाष्ठा को छुआ, उस दौरान सामाजिक एकता ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और समाज के हर वर्ग के लोगों ने उनसे प्रेरणा लेकर सत्य और संस्कृति के प्रति अडिग रहने का संकल्प लिया। उन्होंने कहा, 'श्री गुरु गोविंद सिंह जी की 'गुरु नानक नाम-लेवा संगत' जैसी परंपराओं ने सामाजिक एकता के उस महान यज्ञ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।'

सिख समुदाय और सामाजिक एकता के लिए शुरू की गई पहलों का जिक्र करते हुए श्री मोदी ने ऐसे समागम को एक सतत यात्रा बताया जो पिछले वर्ष नागपुर में शुरू हुई और नांदेड़ के ऐतिहासिक तख्त श्री हजूर साहिब की भूमि पर आगे बढ़ी। उन्होंने कहा, 'नवी मुंबई में इस यात्रा ने एक महत्वपूर्ण पड़ाव पार कर लिया है, जिससे श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी का इतिहास महाराष्ट्र के हर कोने तक, हजारों गांवों और बस्तियों तक पहुंच गया है।' उन्होंने कहा कि साहस और सत्य के साथ खड़े रहने की भावना आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी अतीत में थी। श्री मोदी ने जोर देकर कहा, 'जब नई पीढ़ी इन मूल्यों से जुड़ती है, तो परंपरा केवल एक स्मृति बनकर न रहकर भविष्य का मार्ग बन जाती है।'

साहस और सत्य के साथ खड़े रहने की भावना आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी के समय में थी

राष्ट्रीय एकता के महत्व पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आज जब देश को एक बार फिर सामाजिक एकता की सबसे अधिक आवश्यकता है, तब संगत का यह अद्भुत जमावड़ा देश को आश्वस्त करता है कि गुरुओं और संतों का आशीर्वाद हमारे साथ है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार गुरु साहिबों से संबंधित हर ऐतिहासिक अवसर को राष्ट्रीय स्तर पर मना रही है। श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी के 400वें प्रकाश पर्व और गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व जैसे महत्वपूर्ण अवसरों का जिक्र करते हुए श्री मोदी ने कहा कि प्रत्येक अवसर को पूरी श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। साहिबजादों के सम्मान में प्रतिवर्ष 'वीर बाल दिवस' मनाने की नई राष्ट्रीय परंपरा पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री ने रिकॉर्ड समय में 'करतारपुर साहिब कॉरिडोर' के पूरा होने और 'श्री हेमकुंड साहिब यात्रा' के लिए नई सुविधाओं के निर्माण जैसी उपलब्धियों का जिक्र किया। श्री मोदी ने कहा, 'सरकार ने सिख संस्थाओं और गुरुद्वारों से जुड़े संगठनों को एफसीआरए के तहत राहत प्रदान की है, साथ ही यह सुनिश्चित किया है कि सिख इतिहास को स्कूली पाठ्यक्रम और सांस्कृतिक चर्चा में उचित स्थान मिले, जिससे समुदाय के दशकों से प्रतीक्षित कार्य पूरे हुए हैं।'■

दसों गुरुओं के जीवन से प्रेरणा लेकर धर्म परिवर्तन के विरुद्ध सभी देशवासियों को एकजुट होना चाहिए

सहकार जागरण टीम

श्री गुरु तेगबहादुर जी ने हिंदुओं और पूरे भारत पर जो उपकार किये हैं, उसे कोई नहीं भुला सकता। हिंदू धर्म और इसके अनुयायियों की रक्षा के लिए उन्होंने एक पल की भी देरी नहीं की और अपना सर्वस्व बलिदान दे दिया।' केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने इन विचारों को श्री तेगबहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस समागम समारोह में महाराष्ट्र के नवी मुंबई में व्यक्त किया। गुरु साहिब के जीवन और उनके अद्वितीय पराक्रम को स्मरण व नमन कर श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर गुरु साहिब के 350वें शहीदी दिवस को मनाने का निर्णय लिया, जो कि पूरे देश के लिए सौभाग्य का विषय है। उन्होंने कहा कि अगर नौवें गुरु तेगबहादुर जी हिंदू धर्म और हिंदुओं को बचाने के लिए शहादत न देते तो पूरे विश्व में एक भी हिंदू नहीं बचता। औरंगजेब के शासन के दौरान 1675 में देश ने एक ऐसा बलिदान देखा, जिसने जनता की हिम्मत बढ़ाई और औरंगजेब के अत्याचार की ताकत को तोड़ने का काम किया।

जाति, वर्ग, पंथ और समाज की सभी संकीर्णताओं से ऊपर उठकर प्रत्येक भारतवासी को अपनी संस्कृति के लिए एकजुट होकर संघर्ष करने की प्रेरणा देने वाले गुरु साहिब की जीवनगाथा को याद करते हुए श्री शाह ने कहा कि सरबंसदानी श्री गुरु तेग बहादुर जी सहित दसों गुरुओं ने मानवता, करुणा और संवेदना के जो उच्च आदर्श स्थापित किए हैं, वे प्रत्येक युग में मानव समाज के लिए अनुकरणीय रहेंगे। नानकदेव जी महाराज से लेकर गुरु गोविंद सिंह जी तक सभी गुरूओं ने मुगलों की कई पीढ़ियों से धर्म को बचाने के लिए समाज को ताकत प्रदान किया। गुरु नानकदेव जी महाराज

श्री गुरु नानकदेव जी महाराज से लेकर गुरु गोविंद सिंह जी तक सभी गुरुओं ने मुगलों से धर्म को बचाने के लिए समाज को ताकत दी

ने समाज में ज्ञान का प्रचार-प्रसार किया और कई कुरीतियों को समाप्त किया, गुरु अंगददेव जी ने शिक्षा का प्रसार किया, गुरु अमरदास जी ने सामाजिक समरसता बढ़ाई और गुरु रामदास जी ने अनेक संस्थान स्थापित कर समाज को एक मजबूत आधार दिया। इसीतरह, गुरु अर्जन देव जी ने सांस्कृतिक समावेशिता के लिए काम किया, गुरु हरगोविंद जी साहिब ने भक्ति एवं धर्म की रक्षा का दर्शन दिया और गुरु हरराय जी ने दया भाव को प्रचारित किया। श्री शाह ने कहा कि तेगबहादुर जी ने हिंद की चादर का स्वरूप विश्व के सामने रखा और गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना कर 'गुरु ग्रंथ साहिब' का प्रकाश फैलाया। सिख पंथ के इन गुरुओं ने एक ऐसी परंपरा बनाई है जो न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया के लिए अनुकरणीय है। इन गुरुओं के जीवन से प्रेरणा लेकर धर्म परिवर्तन के विरुद्ध सभी देशवासियों को एकजुट होना चाहिए।

श्री शाह ने कहा कि सिख परंपरा का मूल एकता, बंधुत्व, समावेश और वीरता रहा है और गुरु ग्रंथ साहिब में इसी तत्व का समावेश किया गया है। दशम पिता ने संत नामदेव जी, नरसी मेहता, संत कबीर और रविदास जी जैसे कई संतों के पदों को गुरु ग्रंथ साहिब में जगह दिया है। गुरु नानकदेव जी ने मानवता के तीन सरल सिद्धांत हमें दिए हैं- नाम जपो, कीरत करो और वंड छको। इसका अर्थ है कि ईश्वर के नाम का जाप करते रहिए, उनका कीर्तन करें और साथ में भोजन कीजिए। उन्होंने कहा कि यह आपसी साझेदारी को बताता है और यही परंपरा आगे जाकर लंगर और साझा चूल्हा में परिवर्तित हुई और मुगलों के सामने लड़ने की बहुत बड़ी ताकत मिली। भारत की हजारों साल पुरानी परंपरा को गुरु नानकदेव ने एक नया रूप प्रदान किया। ■

केंद्र सरकार की राजस्थान को हजारों करोड़ की सौगात

प्रधानमंत्री मुफ्त बिजलीघर योजना में राजस्थान का भविष्य बदलने की क्षमता

सहकार जागरण टीम

सरकार समाज के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है। भारत सरकार ने महिलाओं को सहायता प्रदान करने के लिए कई योजनाएं चलाई हैं। ये बातें प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने राजस्थान के अजमेर में राष्ट्रव्यापी एचपीवी टीकाकरण अभियान का शुभारंभ और सड़क, बिजली, जल, स्वास्थ्य, शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में लगभग 17,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास करते हुए कही। श्री मोदी ने शौचालयों, सैनिटरी पैड्स और उज्ज्वला गैस योजना के लिए 'मिशन मोड' समाधानों के सफल कार्यान्वयन का जिक्र करते हुए महिलाओं के स्वास्थ्य और गरिमा के प्रति सरकार के संवेदनशील दृष्टिकोण का वर्णन किया। गर्भावस्था के दौरान पौष्टिक भोजन सुनिश्चित करने के लिए बहनों के खातों में 5,000 रुपए जमा किए जाने का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि यह उपेक्षा की संस्कृति से संवेदनशीलता की संस्कृति की ओर एक कदम है। श्री मोदी ने कहा कि सभी जानते हैं कि जब परिवार में मां बीमार पड़ती है, तो घर बिखर जाता है। मां स्वस्थ रहती है, तो परिवार हर संकट का सामना करने में सक्षम रहता है।

बुनियादी ढांचे पर चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सड़क, रेल और हवाई मार्ग के माध्यम से आधुनिक संपर्क राजस्थान का भविष्य बदल रहा है। बेहतर यात्रा व्यवस्था अजमेर-पुष्कर जैसे स्थानों पर पर्यटन को बढ़ावा दे रही है। इससे स्थानीय व्यवसायों, कारीगरों और टैक्सी चालकों को सीधा लाभ मिल रहा है। दिल्ली-मुंबई औद्योगिक गलियारे के आसपास बन रहा बुनियादी ढांचा राजस्थान को वैश्विक निवेश के लिए 'अवसरों की भूमि' बना रहा है।

एचपीवी टीकाकरण अभियान देश की नारीशक्ति को सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम

> प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने अजमेर से देशभर की 14 वर्ष की बेटियों को सर्वाइकल कैंसर से सुरक्षित करने के उद्देश्य से एचपीवी वैक्सीन के राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान की शुरूआत की। यह महिलाओं में होने वाला दूसरा सबसे सामान्य कैंसर है। इस निःशुल्क टीकाकरण के माध्यम से नारीशक्ति को इस बीमारी से लड़ने में सक्षम बनाया जाएगा और यह कैंसरमुक्त भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा।
>
> **श्री अमित शाह**
> **केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री**

प्रधानमंत्री ने सूर्य से समृद्धि अर्जित करने की राजस्थान की क्षमता का जिक्र करते हुए बताया कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत छतों पर सौर पैनल लगाने के लिए 78,000 रुपए की सहायता प्रदान करने वाली इस योजना से राजस्थान में 1.25 लाख से अधिक परिवार पहले ही जुड़ चुके हैं। इससे कई परिवारों के बिजली बिल लगभग शून्य हो गए हैं। राष्ट्रव्यापी एचपीवी टीकाकरण अभियान का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने इसे भारत की 'नारी शक्ति' को सशक्त बनाने और माताओं तथा बेटियों के स्वास्थ्य को बेहतर करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया।■

पुडुचेरी में विकास परियोजनाओं का लोकार्पण कर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी बोले

युवाओं के सपनों को साकार करने के लिए काम कर रही सरकार

सहकार जागरण टीम

मजबूत और सशक्त युवा हमारी तरक्की की नींव है। हम उनके सपनों को साकार करने के लिए काम कर रहे हैं। ये बातें प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पुडुचेरी ने 2,700 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और लोकार्पण करते हुए कही। एनआईटी कराईकल में नए शुरू हुए डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम इंजीनियरिंग ब्लॉक और मॉडर्न हॉस्टल की सुविधाओं के साथ-साथ पांडिचेरी यूनिवर्सिटी में अवसंरचना की बेहतरी का जिक्र करते हुए श्री मोदी ने कहा कि इससे तकनीकी शिक्षा मजबूत होगी और विद्यार्थियों को मदद मिलेगी। दुनिया के स्वच्छ और ग्रीन मोबिलिटी पर ध्यान देने की चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्तमान में इलेक्ट्रिक गाड़ियां रोजमर्रा की ज़िंदगी का जरूरी हिस्सा बन रही हैं।

हेल्थकेयर को सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कोई भी देश तभी तरक्की कर सकता है जब उसकी मानव पूंजी स्वस्थ हो। स्वास्थ्य सेवा सभी के लिए आसान, उपलब्ध और सस्ती होनी चाहिए। यह सपना आयुष्मान भारत स्कीम के जरिए करोड़ों परिवारों के लिए पहले से ही साकार हो रहा है। पुडुचेरी के किसी भी नागरिक को इलाज के लिए दूर जाने के लिए मजबूर नहीं होना चाहिए। इस इलाके में जहां पहले से ही नौ मेडिकल कॉलेज हैं, मेडिकल टूरिज्म हब बनने की क्षमता है। हेल्थकेयर क्षमता को और बढ़ाने के लिए जेआईपीएमईआर में क्षेत्रीय कैंसर केंद्र को आधुनिक बनाया जा रहा है। इमरजेंसी सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए पुडुचेरी और कराईकल में पीएम-एभीम के तहत तीन क्रिटिकल केयर ब्लॉक की नींव रखी गई है। कराईकल में नया इंटीग्रेटेड आयुष हॉस्पिटल सिद्ध मेडिसिन और होलिस्टिक हेल्थकेयर के लिए इस क्षेत्र की प्रतिष्ठा को और बढ़ाएगा। पुडुचेरी मेडिकल टूरिज्म हब बन सकता है।

- हेल्थकेयर सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता
- पुडुचेरी में मेडिकल टूरिज्म हब बनने की क्षमता
- कनेक्टिविटी है तरक्की की रीढ़

कनेक्टिविटी को तरक्की की रीढ़ बताते हुए प्रधानमंत्री ने बताया कि विद्यार्थियों, किसानों और छोटे बिजनेस के लिए पहुंच को बेहतर बनाने के लिए सैकड़ों किलोमीटर ग्रामीण सड़कें बनाई जा रही हैं। इसके साथ ही पुडुचेरी शहर में भीड़ कम करने के लिए 1,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश किया जा रहा है।

पुडुचेरी जैसे टूरिज्म हब में पीएम ई-बस सेवा के तहत इलेक्ट्रिक बसें प्रदूषण कम करने में गेमचेंजर हो सकती हैं। श्री मोदी ने पुडुचेरी, कराईकल, माहे और यनम में कई सौ करोड़ रुपए की परियोजनाओं के साथ-साथ परिवारों को स्थिरता और सम्मान देने के लिए डिजाइन की गई परियोजनाओं पीने का स्वच्छ पानी सुनिश्चित करने के लिए वॉटर डीसेलिनेशन प्लांट, वेस्ट मैनेजमेंट को बेहतर बनाने के लिए नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और मानसून के दौरान बाढ़ और पानी भरने की समस्या दूर करने के लिए चल रहे कार्यों पर जोर दिया। ■

हरिद्वार में 1132 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण कर बोले श्री अमित शाह

हम धार्मिक रूप से प्रताड़ित हर एक अल्पसंख्यक शरणार्थी को नागरिकता देकर रहेंगे

सहकार जागरण टीम

- **केदारनाथ से लेकर कन्याकुमारी तक एक-एक घुसपैठिए को देश से बाहर निकालेंगे, उत्तराखंड ने 10,000 से अधिक घुसपैठियों के अतिक्रमण हटाए**
- **वर्ष 2014-24 के बीच उत्तराखंड को अनुदान के रूप में एक लाख 87 हजार करोड़ रुपए दिए, 2004-14 तक की सरकार ने सिर्फ 54,000 करोड़ दिए**

उत्तराखंड विकास के रास्ते पर 'दिन दूनी रात चौगुनी' गति से आगे बढ़ रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने उत्तराखंड को बनाया और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने इसे संवारने का काम कर रहे हैं। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने इन विचारों को हरिद्वार में 1132 करोड़ रुपए से अधिक के जनकल्याणकारी कार्यों को जनता को अर्पित करने और कुछ योजनाओं के शुभारंभ के दौरान व्यक्त किया और कहा कि ये परियोजनाएं 'विकसित उत्तराखंड' के निर्माण में मील का पत्थर सिद्ध होंगी। श्री शाह ने कहा कि अटल जी के बनाए उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड राज्य विकास की राह पर आगे बढ़ रहे हैं। इनमें बीते नौ वर्ष उत्तराखंड राज्य में हमारी सरकार के दौरान विकास के स्वर्णिम वर्ष रहे हैं।

श्री शाह ने कहा कि 2027 में देवभूमि के हरिद्वार में कुंभ का आयोजन होना है, जो कि पूरे भारत की शान है और इसके लिए भारत सरकार ने राज्य को बड़ी धनराशि उपलब्ध कराई है। राज्य की वर्तमान सरकार की चार वर्षीय स्वर्णिम यात्रा को दर्शाती प्रदर्शनी का लोकार्पण कर श्री शाह ने कहा कि उत्तराखंड विकास के कीर्तिमान बना रहा है और अपनी विरासतों व परंपराओं को भी सहेज रहा है। राज्य में चार धाम यात्रियों की संख्या में तीन गुना वृद्धि करने वाली, उत्तराखंड के हर कस्बे को रोड से जोड़ने का प्रयास करने वाली, युवाओं को बिना खर्ची-बिना पर्ची नौकरी देने वाली, कॉमन सिविल कोड लाने वाली, सीएए के माध्यम से नागरिकता देने वाली और घुसपैठियों को चुन-चुन कर निकालने का संकल्प लेने वाली सरकार है। श्री शाह ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यकाल के विकास संबंधी विकल्प रहित संकल्प पुस्तक का विमोचन भी किया, जिसे गिरिजा शंकर जोशी ने संपादित किया है।

देवभूमि का विकास सरकार की प्राथमिकता

श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी ने 2014 से 2024 तक उत्तराखंड को अनुदान के तौर पर एक लाख 87 हजार करोड़ रुपए दिया है, जबकि पूर्ववर्ती सरकार ने वर्ष 2004 से 2014 तक राज्य को सिर्फ 54,000 करोड़ रुपए ही दिए। इसके साथ ही हमारी सरकार ने केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री

यानि 900 किलोमीटर के चार धाम महामार्ग के लिए 12 हजार करोड़ रुपए, दिल्ली-देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए आठ हजार करोड़ रुपए, उत्तराखंड में 30 राष्ट्रीय राजमार्गों का पांच हजार करोड़ रुपए से निर्माण और 2200 करोड़ रुपए से टनकपुर में आठ मार्गों के निर्माण एवं नजीबाबाद, अफजलगढ़ बाईपास, पुरकाजी, लक्सर और हरिद्वार रोड के नवीनीकरण के लिए भी धनराशि दिए हैं। कृषि और मत्स्य पालन के क्षेत्र में भी राज्य में बहुत से कार्य हुए हैं।

श्री शाह ने जोर देकर कहा कि 2014 में उत्तराखंड की प्रति व्यक्ति आय 1,80,000 रुपए थी, जो बढ़कर अब 2,74,000 हो गई है। उत्तराखंड की सकल राज्य घरेलू उत्पाद भी 2,22,000 करोड़ रुपए से बढ़कर अब 3,82,000 करोड़ रुपए हो चुकी है। राज्य के करीब 10 लाख से अधिक किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना का लाभ मिला है, 14 लाख से अधिक घरों को जल जीवन मिशन का फायदा मिल रहा है और 62 लाख लोगों को आयुष्मान योजना के तहत पांच लाख तक के मुफ़्त इलाज का फायदा मिला है। राज्य में 5,80000 घरों में शौचालय बना है और 60 लाख लोगों को प्रतिमाह प्रति व्यक्ति पांच किलो अनाज मुफ्त में मिलता है। सरकार ने यहां 5,33000 माताओं-बहनों को गैस सिलेंडर प्रदान किया है।

जहां वर्ष 2009 से 2014 के दौरान उत्तराखंड का औसत रेल बजट 187 करोड़ रुपए था, वहीं पिछले नौ वर्षों में यह बढ़कर लगभग 4770 करोड़ रुपए हो चुका है। श्री शाह ने कहा कि हमारी सरकार ने राज्य को 26000 करोड़ रुपए की लागत से तीन नए रेलवे प्रोजेक्ट दिए हैं, 300 किलोमीटर रेलमार्ग का विद्युतीकरण हुआ है, 147 करोड़ रुपए की लागत से 11 अमृत स्टेशन विकसित हो रहे हैं और 100 फ्लाईओवर और अंडर ब्रिज बने हैं। ऋषिकेश से कर्णप्रयाग के बीच सबसे बड़ी रेल सुरंग बनाई गई है और कई सारे हेलीपैड भी बने हैं। देहरादून एयरपोर्ट को आधुनिक बनाया गया है। पर्वतमाला रोपवे विकास कार्यक्रम के लिए 2400 करोड़ रुपए दिए गए हैं।

संस्कृति से जुड़े कामों को पूरा किया

श्री शाह ने कहा कि श्री मोदी के नेतृत्व में सरकार ने हमारी संस्कृति से जुड़े और कई सालों से लंबित कामों को पूरा किया है, जिनमें कश्मीर से धारा 370 समाप्त करना, हिंदू शरणार्थियों के लिए सीएए कानून लाना और 550 वर्षों से अयोध्या में श्रीरामलला का मंदिर बनाने की हिंदू समाज की लालसा को पूरा करने का काम शामिल है। केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम में पूरे शहर की पुनर्रचना कराई गई है, उज्जैन में महाकाल लोक बनाया है और औरंगजेब द्वारा तोड़े गए काशी विश्वनाथ के कॉरिडोर को भी सरकार ने बनवाया है।

यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बना उत्तराखंड

पूरे देश में जहां-जहां घुसपैठिये हैं, हम केदारनाथ धाम से लेकर कन्याकुमारी तक एक-एक घुसपैठिये को चुन-चुन कर भारत से बाहर निकालेंगे। श्री शाह ने कहा कि उत्तराखंड की राज्य सरकार ने लगभग 10,000 से ज्यादा अतिक्रमण उखाड़ कर फेंक दिए हैं। उत्तराखंड सरकार तुष्टीकरण समाप्त करने की दिशा में कदम उठाते हुए यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आई है, जिससे नागरिक का धर्म कोई भी हो, उसे एक ही कानून के तहत देश में रहना होगा। इस तरह, उत्तराखंड देश भर में यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बना है।

नकल विरोधी कानून से रोजगार के क्षेत्र में पारदर्शिता

राज्य के 1900 नवनियुक्त युवाओं को पुलिस कांस्टेबल की नौकरी पत्र देकर श्री शाह ने कहा कि हमारी सरकार ने इन युवाओं को बिना किसी सिफारिश की पर्ची और खर्ची के योग्यता के आधार पर चयन किया है। पारदर्शी प्रक्रिया से नियुक्त ये पुलिस कर्मी नए कानूनों को जमीन पर उतारकर प्रदेश में सुशासन और जनसुरक्षा को और मजबूत करेंगे। राज्य में सुशासन पर संतोष व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि पहाड़ पर रहने वाली किसी बूढ़ी मां का बेटा बगैर किसी सिफारिश के नौकरी प्राप्त कर अपने घर जा रहा है।

162 शरणार्थियों को नागरिकता प्रमाण पत्र

पाकिस्तान और अफगानिस्तान के 162 शरणार्थियों को नागरिकता प्रमाण पत्र प्रदान कर श्री शाह ने कहा कि अब ये लोग भारत के नागरिक बनकर अपने धर्म और संस्कृति की रक्षा करते हुए गरिमापूर्ण जीवन जी सकेंगे। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से आए हिन्दू, सिख, बौद्ध और जैन शरणार्थियों का इस देश पर उतना ही अधिकार है जितना इस देश के नागरिकों का अधिकार है, क्योंकि ढेर सारी यातनाएं झेलकर वे हमारे देश में अपना धर्म और अपने परिवारों की महिलाओं का सम्मान बचाने के लिए शरणार्थी बनकर आए हैं।■

गुजरात में सेमीकंडक्टर इकाई का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी बोले

सेमीकंडक्टर में आत्मनिर्भर बन रहा है भारत

सहकार जागरण टीम

सेमीकंडक्टर क्षेत्र के विकास के प्रति भारत प्रतिबद्ध है। सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत 10 परियोजनाओं को मंजूरी मिल चुकी है, जबकि तीन और परियोजनाएं उत्तर प्रदेश, असम, ओडिशा और पंजाब सहित विभिन्न राज्यों में शीघ्र ही उत्पादन शुरू करने के लिए तैयार हैं। विकसित भारत' के लिए देश के हर कोने में नए तकनीकी केंद्र विकसित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने गुजरात के साणंद में एक सेमीकंडक्टर इकाई का उद्घाटन करते हुए यह विचार व्यक्त किया।

सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम में मशीन निर्माता, डिजाइन इंजीनियर, अनुसंधान संस्थान, लॉजिस्टिक्स नेटवर्क और कुशल तकनीशियन के शामिल होने और इन सभी तत्वों के सुचारू समन्वय से ही चिप का उत्पादन होने का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, भारत संपूर्ण मूल्य श्रृंखला पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। इसी उद्देश्य से बजट में 'इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0' की घोषणा की गई है। उत्पादन बढ़ने के साथ-साथ भारत में सामग्रियों, घटकों और सेवाओं की मांग भी बढ़ेगी। यही सबसे बड़ा अवसर है।

'मेक इन इंडिया' अभियान के पूरी रफ्तार से चलने और पिछले 11 वर्षों में इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र के उत्पादन और निर्यात में हुई कई गुना वृद्धि का जिक्र करते हुए श्री मोदी ने कहा कि निवेशकों के लिए घरेलू और वैश्विक बाजार दोनों में ही अवसर मौजूद हैं। साणंद में माइक्रोन संयंत्र एक नए सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का आधार बनेगा। यह संयंत्र वैश्विक डेटा केंद्रों, एआई अनुप्रयोगों और मोबाइल उपकरणों को शक्ति प्रदान करने के लिए डी-रैम और नैंड समाधानों का उत्पादन करेगा। सेमीकंडक्टर क्षेत्र के लिए बनाई गई नीतियां अब जमीनी स्तर पर परिणाम दे रही हैं। गुजरात प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में तेजी से प्रगति कर रहा है। अनुमोदन, भूमि आवंटन और उपयोगिताओं जैसी प्रक्रियाओं को सरल बनाने से निवेशकों का विश्वास बढ़ा है। धोलेरा और साणंद पश्चिमी भारत के सेमीकंडक्टर क्लस्टर के रूप में विकसित हो रहे हैं। सेमीकंडक्टर क्षेत्र के लिए आवश्यक इनपुट, जैसे रसायन और पेट्रोकेमिकल्स से संबंधित उद्योगों के साथ-साथ कौशल केंद्र और प्रशिक्षण पहल भी साथ-साथ विकसित किए जा रहे हैं।

सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में अपनी शक्ति के लिए जाना जाने वाला भारत अब हार्डवेयर क्षेत्र में भी अपनी पहचान को कर रहा सशक्त

भारत तैयार है, भारत भरोसेमंद है, भारत परिणाम देता है कहते हुए प्रधानमंत्री ने इस दशक को भारत के तकनीकी विकास के लिए एक ऐतिहासिक मोड़ बताया। 'भारत सक्षम है। भारत प्रतिस्पर्धी है। भारत प्रतिबद्ध है।'

श्री मोदी ने कहा कि जहां भारत कभी मुख्य रूप से सॉफ्टवेयर और आईटी सेवाओं के लिए जाना जाता था, वहीं अब वह हार्डवेयर क्षेत्र में तेजी से अपनी पहचान मजबूत कर रहा है। साणंद में हम एक नए भविष्य की शुरुआत देख रहे हैं। माइक्रोन के एटीएमपी केंद्र में वाणिज्यिक उत्पादन की शुरुआत वैश्विक प्रौद्योगिकी मूल्य श्रृंखला में भारत की भूमिका को मजबूत करने के लिए तैयार है। नियमों व प्रक्रियाओं को काफी हद तक सरल बनाने का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि जब इरादा स्पष्ट होता है और राष्ट्र के तीव्र विकास के प्रति समर्पण होता है, तो नीतियां पारदर्शी हो जाती हैं और निर्णय गति पकड़ते हैं। वर्तमान सदी एआई क्रांति की सदी है। सेमीकंडक्टर इस बदलाव का सेतु है। यदि 20वीं सदी में तेल नियामक था तो 21वीं सदी में माइक्रोचिप नियामक है। एक छोटी सी चिप औद्योगिक क्रांति को एआई क्रांति से जोड़ने का माध्यम है। इसी सोच के साथ भारत ने सेमीकंडक्टर क्षेत्र में आक्रामक रूप से आगे बढ़ने का निर्णय लिया है।■

कृषि को मजबूती देने से किसानों को मिली आर्थिक सुरक्षा : प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

सहकार जागरण टीम

कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार और देश के दीर्घकालिक विकास का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। 'पीएम किसान सम्मान निधि' और 'न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी)' जैसे कई योजनाओं से किसानों को डेढ़ गुना लाभ मिल रहा है। सरकार ने कृषि क्षेत्र को लगातार मजबूत किया है। सरकार के प्रयासों से किसानों के जोखिम कम हुए हैं और उन्हें बुनियादी आर्थिक सुरक्षा मिली है। ये बातें प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने संसद के बजट सत्र के दौरान बजट पर आयोजित वेबिनार को संबोधित करते हुए कही। वैश्विक मांग में हो रहे बदलावों और भारतीय कृषि को निर्यात-उन्मुख बनाने की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने उत्पादकता और निर्यात क्षमता बढ़ाने के लिए भारत की विविध जलवायु का पूर्ण उपयोग करने का आह्वान किया।

उच्च मूल्य वाली कृषि पर ध्यान केंद्रित करते हुए प्रधानमंत्री ने कोको, काजू और चंदन जैसी फसलों पर जोर दिया। पूर्वोत्तर में अगरवुड और हिमालयी राज्यों में शीतोष्ण मेवों की फसलों को बढ़ावा देने की बात कहते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि निर्यात उन्मुख उत्पादन से प्रसंस्करण और मूल्यवर्धन के माध्यम से ग्रामीण रोजगार सृजित होगा। इससे हमारा कृषि क्षेत्र वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बन सकेगा। खाद्यान्न और दालों के रिकॉर्ड उत्पादन का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने इस क्षेत्र में नई ऊर्जा भरने का आह्वान किया।

मत्स्य पालन क्षेत्र का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है। हमारे जलाशयों और तालाबों में वर्तमान में लगभग 4.5 लाख टन मछली का उत्पादन हो रहा है, जबकि अतिरिक्त 20 लाख टन उत्पादन की संभावना है। मत्स्य पालन, निर्यात बढ़ाने का एक प्रमुख आधार बन सकता है। समुद्री अर्थव्यवस्था की क्षमता को साकार करने के लिए हैचरी, चारा और लॉजिस्टिक्स में नए व्यावसायिक मॉडलों की आवश्यकता है। मत्स्य पालन ग्रामीण समृद्धि के लिए एक उच्च मूल्य और उच्च प्रभाव वाला क्षेत्र बन सकता है।

- **उच्च मूल्य वाली कृषि को बढ़ावा देने से यह क्षेत्र दुनिया में बनेगा प्रतिस्पर्धी**
- **निर्यात उन्मुख उत्पादन बढ़ने से प्रसंस्करण और मूल्यवर्धन से होगा रोजगार का सृजन**

दूध उत्पादन में दुनिया में भारत का पहला और अंडा उत्पादन में दूसरा स्थान होने का जिक्र करते हुए श्री मोदी ने कहा कि इसे और आगे ले जाने के लिए गुणवत्तापूर्ण प्रजनन, रोग निवारण और वैज्ञानिक प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है। जब वह 'एक पृथ्वी, एक स्वास्थ्य' की बात करते हैं तो इसमें पशुधन का स्वास्थ्य भी शामिल है। वैक्सीन उत्पादन के मामले में देश की आत्मनिर्भरता का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत प्रौद्योगिकी के विस्तार और पशुपालन करने वाले किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड की उपलब्धता का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि पशुओं को मुंहपका-खुरपका बीमारी से बचाने के लिए 125 करोड़ से अधिक खुराकें दी जा चुकी हैं। पशुपालन अवसंरचना विकास कोष भी शुरू किया गया है। जोखिमों को कम करने के लिए फसल विविधीकरण की वकालत करते हुए खाद्य तेल, दालों और प्राकृतिक खेती के लिए चलाए जा रहे अभियानों को इस क्षेत्र की मजबूती बढ़ाने के साधन के रूप में बताया।

कृषि में 'प्रौद्योगिकी संस्कृति' लाने की बात करते हुए श्री मोदी ने ई-एनएएम और डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के विकास का जिक्र किया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित प्लेटफार्मों और डिजिटल सर्वेक्षणों की भूमिका का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रौद्योगिकी तभी परिणाम देती है जब संस्थानों और उद्यमियों द्वारा इसे अपनाया जाता है। ■

सहकारी चुनावों में पारदर्शिता और शुचिता सुदृढ़ करने के लिए राष्ट्रीय संगोष्ठी

सहकारिता में सुधारों को मिल रही गति

सहकार जागरण टीम

- **सहकारी संस्थाओं में लोकतांत्रिक शासन को मिल रही मजबूती, सहकारी चुनाव प्राधिकरण ने अब तक 240 चुनाव सम्पन्न कराए**
- **महिलाओं तथा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण से सहकारी संस्थाओं के प्रबंधन में बढ़ रही समावेशिता**

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 'सहकार से समृद्धि' के विजन और केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के नेतृत्व में भारत सरकार सहकारी तंत्र को सशक्त व समर्थ बना रही है। देश में सतत सहकारी विकास के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने की दिशा में निरंतर कार्य हो रहा है, जिससे आत्मनिर्भर और विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहकारिताओं महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकें। केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री श्री कृष्ण पाल गुर्जर ने इन विचारों को नई दिल्ली में विज्ञान भवन में सहकारिता मंत्रालय के तहत आयोजित एक राष्ट्रीय संगोष्ठी के दौरान व्यक्त किया। सहकारी चुनावों में पारदर्शिता और शुचिता को सुदृढ़ बनाने को लेकर विचार-विमर्श के लिए सहकारी चुनाव प्राधिकरण (सीईए) के आयोजन में श्री गुर्जर ने कहा कि पहली बार देशभर की बहु-राज्यीय सहकारी समितियों के प्रतिनिधि एक ही मंच पर एकत्रित हुए हैं और यह ऐतिहासिक कार्यक्रम सहकारी आंदोलन के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर सिद्ध होगा।

सहकारी समितियां सहकारी सिद्धांतों पर आधारित होती हैं, जो सहकारी आंदोलन के विकास और सुदृढ़ीकरण के लिए एक मजबूत ढांचा प्रदान करते हैं। इन सिद्धांतों के अनुसार सदस्य समान रूप से योगदान देते हैं और सहकारी संस्थाओं की पूंजी तथा कार्यप्रणाली पर लोकतांत्रिक नियंत्रण रखते हैं, जिससे वे नीतिगत निर्णयों और प्रबंधन प्रक्रियाओं में सक्रिय भागीदारी कर पाते हैं। सहकारिता राज्यमंत्री श्री शाह ने सहकारी व्यवस्था में जनता का विश्वास बढ़ाने की जरूरत पर बल देते हुए कहा कि सहकारी संस्थाओं में पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासनिक ढांचा विकसित करना आवश्यक है। उन्होंने भर्ती और वस्तुओं तथा सेवाओं की खरीद के लिए पारदर्शी और योग्यता आधारित प्रणाली अपनाने पर जोर दिया, जिससे सहकारी संस्थाएं पेशेवर ढंग से संचालित आर्थिक इकाइयों के रूप में विकसित होकर विकसित भारत के लक्ष्य में योगदान दे सकें।

सहकारी बैंकिंग क्षेत्र में लोकतांत्रिक शासन

बैंकिंग विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 2025 के जरिए बहु-राज्यीय सहकारी बैंकों सहित अन्य सहकारी बैंकों के बोर्ड के कार्यकाल को संविधान की व्यवस्था के अनुरूप किया गया है। इसप्रकार से सहकारी बैंकिंग क्षेत्र में लोकतांत्रिक शासन को और सुदृढ़ किया गया है। मल्टी-स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज (संशोधन) अधिनियम, 2023 के तहत सहकारी बैंकों में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए यह प्रावधान किया गया है कि ऐसे बैंक अपने लेखा परीक्षकों की नियुक्ति केंद्रीय रजिस्ट्रार द्वारा स्वीकृत पैनल से करें। इससे सहकारी बैंकिंग क्षेत्र में लेखा परीक्षा प्रणाली को मजबूत करने और वित्तीय अनुशासन को बढ़ावा मिलेगा। अब बहु-राज्यीय सहकारी बैंकों के निदेशक लगातार दस वर्षों से अधिक समय तक पद पर नहीं रह सकेंगे, जिससे सहकारी संस्थाओं के प्रबंधन में नए और युवा नेतृत्व के लिए अवसर उपलब्ध होंगे।

सहकारिता राज्य मंत्री ने यह भी बताया कि मल्टी-स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज अधिनियम, 2002 में संशोधन के बाद सहकारी समितियों के सदस्यों के हितों की रक्षा के उद्देश्य से 5 मार्च 2024 की राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से सहकारी लोकपाल की नियुक्ति की गई है। सहकारी लोकपाल सहकारी समितियों के सदस्यों द्वारा दायर शिकायतों की जांच करता है तथा समितियों के सहकारी सूचना अधिकारियों के आदेशों के विरुद्ध दायर अपीलों के लिए अपीलीय प्राधिकारी के रूप में भी कार्य करता है। उन्होंने बताया कि अब तक 38 हजार से अधिक शिकायतें प्राप्त हो चुकी हैं, जिनमें से बड़ी संख्या में शिकायतों का समाधान सहकारी लोकपाल द्वारा पारित आदेशों के माध्यम से किया जा चुका है।

इस अवसर पर सहकारी चुनाव प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री देवेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि प्राधिकरण अपने तीसरे वर्ष में प्रवेश कर रहा है और इस अवधि में देशभर में विभिन्न सहकारी संस्थाओं के चुनाव सफलतापूर्वक सम्पन्न कराकर महत्वपूर्ण अनुभव प्राप्त किया है। सहकारी संस्थाएं लोकतांत्रिक सदस्य नियंत्रण के सिद्धांत पर आधारित होती हैं, इसलिए चुनाव प्रक्रिया का पारदर्शी, सहभागी और विश्वसनीय होना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि सहकारी समितियों के उपनियमों में स्पष्टता होना जरूरी है, जिससे चुनावों के दौरान विवादों से बचा जा सके। मतदान का अधिकार, सक्रिय सदस्यता तथा चुनाव लड़ने की पात्रता जैसे विषयों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए, ताकि चुनाव प्रक्रिया निष्पक्ष और स्पष्ट बनी रहे। इसके अलावा, बड़े बहु-राज्यीय सहकारी संस्थानों में निदेशक मंडल की संरचना ऐसी होनी चाहिए जो सदस्यता की विविधता को प्रतिबिंबित करे और विभिन्न क्षेत्रों का उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करे।

बहु-राज्यीय सहकारी समितियों के अध्यक्ष, मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा निदेशक मंडल के सदस्य, रिटर्निंग अधिकारी, जिला मजिस्ट्रेट, राज्य सहकारी चुनाव प्राधिकरणों के अध्यक्ष, सहकारी क्षेत्र के विशेषज्ञ तथा केंद्र एवं राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारियों सहित विभिन्न हितधारकों ने भाग लिया।

बहु-राज्यीय सहकारी समितियों में स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव

सहकारिता राज्य मंत्री श्री गुर्जर ने कहा कि सहकारी संस्थाओं में लोकतांत्रिक शासन और जवाबदेही को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से सरकार ने अनेक अहम फैसले और सुधार किए हैं। मल्टी-स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज (संशोधन) अधिनियम, 2023 के माध्यम से किए गए इन महत्वपूर्ण सुधारों का उद्देश्य सहकारी संस्थाओं को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और लोकतांत्रिक बनाना है। महत्वपूर्ण सुधारों के इस क्रम में स्वतंत्र सहकारी चुनाव प्राधिकरण की स्थापना भी की गई, जिसे 11 मार्च 2024 को औपचारिक रूप से अधिसूचित किया गया। इस प्राधिकरण को बहु-राज्यीय सहकारी समितियों में स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दी गई है।

एक अन्य महत्वपूर्ण सुधार के तहत बहु-राज्यीय सहकारी समितियों के निदेशक मंडलों के कार्यकाल की निश्चित समयसीमा तय की गई और उन प्रावधानों को समाप्त कर दिया गया, जिनके कारण चुनाव होने तक अनिश्चित समय तक बोर्ड प्रभावी बना रहता था। इस सुधार के जरिए सहकारी संस्थाओं के चुनावों में अनावश्यक विलंब की प्रवृत्ति पर रोक लगी है और उनके प्रशासन में भी अनुशासन आया है।

सहकारी चुनाव प्राधिकरण ने अब तक करीब 240 चुनाव सफलतापूर्वक संपन्न कराए हैं और वित्तीय वर्ष 2026-27 में भी करीब 130 सहकारी संस्थाओं में चुनाव कराए जाने की संभावना है। अब तक कराए गए चुनावों में महिलाओं के लिए आरक्षित छह सीटें और अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए आरक्षित तेरह सीटें अभी रिक्त हैं, जिन्हें भरने के लिए सहकारिता मंत्रालय आवश्यक कदम उठा रहा है। इस प्रकार से सहकारी क्षेत्र में लोकतांत्रिक व्यवस्था मजबूत किया जा रहा है।

संशोधित अधिनियम के तहत निदेशक मंडल में महिलाओं के लिए दो तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए एक-एक सीट आरक्षित किए गए हैं। इससे सहकारी संस्थाओं के प्रबंधन में विविधता और समावेशिता सुनिश्चित हो रही है।■

डॉ. मंगला राय

सहकारिता की पहल से बढ़ेगी अन्न भंडारण क्षमता

भारत दुनिया के सबसे अधिक खाद्यान्न उत्पादक देशों में से एक है। चीन के बाद यहां सबसे अधिक खाद्यान्न का उत्पादन किया जाता है, लेकिन पर्याप्त भंडारण के अभाव में कुल उत्पादन का एक बहुत बड़ा भाग नष्ट हो जाता रहा है। इससे एक ओर जहां खाद्य सुरक्षा को खतरा पैदा हो जाता है, वहीं किसानों उनकी मेहनत का पूरा प्रतिफल नहीं मिल पाता। इस गंभीर समस्या के समाधान के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के सहकार से समृद्धि के विजन के तहत देश के पहले सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के नेतृत्व व मागदर्शन में सहकारिता के क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना बनाई गई। अब इस योजना को प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियों के माध्यम से मूर्त रूप दिया जा रहा है। अन्न भंडारण के लिए गांव-गांव में गोदाम बनाए जा रहे हैं।

वर्ष 2021 में सहकारिता मंत्रालय के गठन के बाद देश में सहकारी समितियों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। इसके साथ ही खाद्यान्न भंडारण क्षमता बढ़ाने की दिशा में सहकारिता मंत्रालय अहम भूमिका निभा रहा है। एक लाख करोड़ रुपए की लागत से दुनिया की सबसे बड़ी पीएम अन्न भंडारण योजना शुरू की गई है। इसके निर्माण और संचालन का पूरा दायित्व सहकारी क्षेत्र पर डाल दिया गया है। प्राथमिक सहकारी समितियों की भागीदारी से खाद्यान्न भंडारण की क्षमता विस्तार होने से देश की खाद्य सुरक्षा को मजबूत बनाने में बहुत मदद मिलेगी। इसके तहत ग्राम पंचायत स्तर पर गोदाम बनाने की योजना पर अमल शुरू कर दिया गया है। दरअसल, पुराने सहकारी गोदामों में जहां पहले गरीब किसानों को उनकी जरूरत के हिसाब से फसल की बोआई के समय अनाज उधार में दिया जाता था, उसकी जगह अब किसानों के सरप्लस अनाज को नए गोदामों में रखा जाएगा। किसानों को उनकी खेती की जरूरतों के लिए उधारी के रूप में नगदी दी जाती है। देश में सहकारिता के अनेक उत्कृष्ट उदाहरण स्थापित हो रहे हैं। कृषि और दुग्ध के क्षेत्र में भारत के अनेक सहकारी ब्रांडों की दुनिया में मिसाल दी जाती है। किसानों को बिचौलियों और सूदखोरों से बचाने के लिए रियायती दरों पर उन्हें पर्याप्त ऋण भी प्रदान किया जा रहा है।

भारत में सहकारिता का इतिहास बहुत पुरना व समृद्ध है। आजादी से पूर्व भी भारत के कई भागों में सहकारिता का प्रचलन था। इसकी अवधारणा और सहकारिता पर आधारित गतिविधियां लोगों के सहकारी जीवन के अंग के रूप में व्यवहार में अपनाई जाती थी। ग्रामीण एक-दूसरे के साथ मिलजुलकर कुओं, जलाशयों का निर्माण व वनों का विकास करते थे। ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को जोड़कर समूह बनाने के पीछे का विचार यह था कि नई और स्वैच्छिक महत्वपूर्ण समझ बन सके। इससे समूह गारंटी प्रस्तुत कर सकेंगे और ऋणदाताओं को भी व्यक्ति की बजाए समूह को ऋण देना कम जोखिम भरा लगेगा। इस दिशा में एक लंबी विकास यात्रा के बाद देश में सहकारी ऋण समिति अधिनियम के माध्यम से कानून बना। शुरू में यह केवल ऋण संबंधी सहकारी संगठनों तक सीमित था। वर्ष 1911 तक भारत में 5300 समितियों का गठन हो चुका था। इनमें तीन लाख से अधिक सदस्य थे।

देश की आजादी के बाद सहकारिता के विकास को बल मिला। योजना आयोग द्वारा निर्धारित विभिन्न योजनाओं में सहकारी समितियों को महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान की गई। सामुदायिक विकास के सभी पहलुओं को समेटने के लिए संगठन की सहकारी पद्धति को अपनाने पर बल दिया गया। इसने शहरी सहकारी बैंकों, कामगारों की सहकारी समितियों, उपभोक्ता सहकारी समितियों, आवास सहकारी समितियों, सहकारी प्रशिक्षण तथा शिक्षा के माध्यम से ज्ञान के प्रसार की व्यवस्था की गई। सहकारिता राज्य का विषय होने तथा प्रत्येक राज्य में अपने सहकारिता संबंधी कानून होने के कारण मॉडल सहकारी समिति अधिनियम के मसौदे को सभी राज्य सरकारों को विचार करने तथा उसे राज्य स्तर पर लागू करने के लिए भेजा गया। सहकारी समितियों की सामूहिकता को बढ़ावा देने और देश के सामाजिक पूंजी आधार को संरक्षित करने में एक अग्रणी भूमिका है।

वास्तव में, सामूहिकता और लोकतंत्र की भावना को बनाए रखने के लिए सहकारिता सबसे अच्छा माध्यम है। सहकारी समितियों जैसे सामाजिक संगठनों के एक बड़े नेटवर्क की उपस्थिति, पूंजी के निर्माण और उपयोग में सहायक होगी तथा 'जितनी अधिक सामाजिक पूंजी होगी, विकास की संभावना उतनी ही अधिक होगी'।■

पूर्व महानिदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद

नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया (एनसीयूआई) के नई दिल्ली कैंपस में भगिनी निवेदिता कॉलेज के छात्रों के लिए सहकारिता पर जागरुकता प्रोग्राम संपन्न हुआ, जहां संस्था के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रितेश डे और डिप्टी डायरेक्टर अनंत दुबे ने छात्रों को सहकारिता क्षेत्र में हो रहे तेज विकास, सहकारी पहलों, कोऑपरेटिव बिजनेस मॉडल, नवाचार और डिजिटलीकरण में युवाओं की भूमिका के बारे में जानकारी दी।

नेशनल सेंटर फॉर कोऑपरेटिव एजुकेशन (एनसीसीई) ने सहकारिता और सहकारी प्रबंधन विषय पर गुजरात के कलोल में इफको प्लांट के अधिकारियों के लिए दो दिवसीय ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित किया, जहां सहकारिता मंत्रालय की महत्वपूर्ण पहलों को सूचना तकनीक के प्रयोग और सोशल मीडिया के जरिए नई स्कीमों के बारे में जागरूकता फैलाने पर भी जोर दिया गया।

मेघालय के प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) के अधिकारियों और सदस्यों के लिए चल रहे प्रबंधन विकास कार्यक्रम के एक हिस्से के रूप में इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट, आनंद और 'त्रिभुवन' सहकारी विश्वविद्यालय ने प्रतिभागियों की सहकारी प्रबंधन की व्यावहारिक समझ बढ़ाने के लिए एक सत्र आयोजित किया, जिसमें कोऑपरेटिव इकोसिस्टम के बारे व्यावहारिक जानकारी दी गई।

एनसीयूआई के एनसीसीई ने ट्रेनिंग प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर पश्चिम बंगाल के प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के प्रतिभागियों के लिए नई दिल्ली के कृभको का एक स्टडी विज़िट आयोजित किया, जहां मिट्टी और बीज टेस्टिंग लैब जाकर प्रतिभागियों ने मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन, नवाचार और सतत सहकारी विकास के बारे में व्यावहारिक जानकारी अर्जित की।

कोऑपरेटिव के जरिए नागालैंड में अच्छी क्वालिटी के बीजों की पहुंच बढ़ाने और कृषि क्षेत्र में टिकाऊ विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड (बीबीएसएसएल) और नागालैंड स्टेट कोऑपरेटिव मार्केटिंग एंड कंज्यूमर फेडरेशन (माकोर्फेड) के बीच नई दिल्ली के बीबीएसएसएल ऑफिस में एक अनुबंध किया गया। बीबीएसएसएल के प्रबंध निदेशक श्री चेतन जोशी, माकोर्फेड के चेयरमैन डॉ. एम. चुबा और माकोर्फेड के प्रबंध निदेशक श्री आर. बेंडांग ने इस भागीदारी के सहभागी बने।

नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड (एनडीडीबी) ने सेंट्रल सुपारी और कोको मार्केटिंग एंड प्रोसेसिंग को-ऑपरेटिव लिमिटेड, कर्नाटक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए ओरिएंटेशन प्रोग्राम आयोजित किया, जिसका उद्देश्य सहकारी कामकाज को अधिक प्रभावी बनाने के लिए लीडरशिप, गवर्नेंस क्षमताओं और इंस्टीट्यूशनल समझ को मजबूत करना था। प्रतिभागियों ने कोऑपरेटिव सेक्टर में प्रोसेसिंग ऑपरेशन और प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए इंस्टिट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट आनंद (इरमा), अमूल डेयरी और मोगर में चॉकलेट प्लांट का दौरा भी किया।

दशकों से गांवों में हमारी बहनों के पास हुनर भी था, मेहनत भी थी, लेकिन उन्हें पूंजी और अवसर नहीं मिलते थे। इसीलिए हमने इन बहनों को सेल्फ हेल्प ग्रुप्स से जोड़ा, बैंकों से जोड़ा और उन्हें नई ट्रेनिंग, नए अवसर और बाजार से जोड़ने का काम किया। आज देश में 10 करोड़ से अधिक बहनें ऐसे समूहों से जुड़ी हुई हैं। इन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को लाखों करोड़ रुपए की आर्थिक मदद मिली है। इसका परिणाम यह है कि आज गांवों की नारीशक्ति आत्मनिर्भर बन रही हैं, अपने परिवार की आय बढ़ा रही हैं और लखपति दीदी बनकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी बहुत मजबूत कर रही हैं।

- श्री नरेन्द्र मोदी,
प्रधानमंत्री

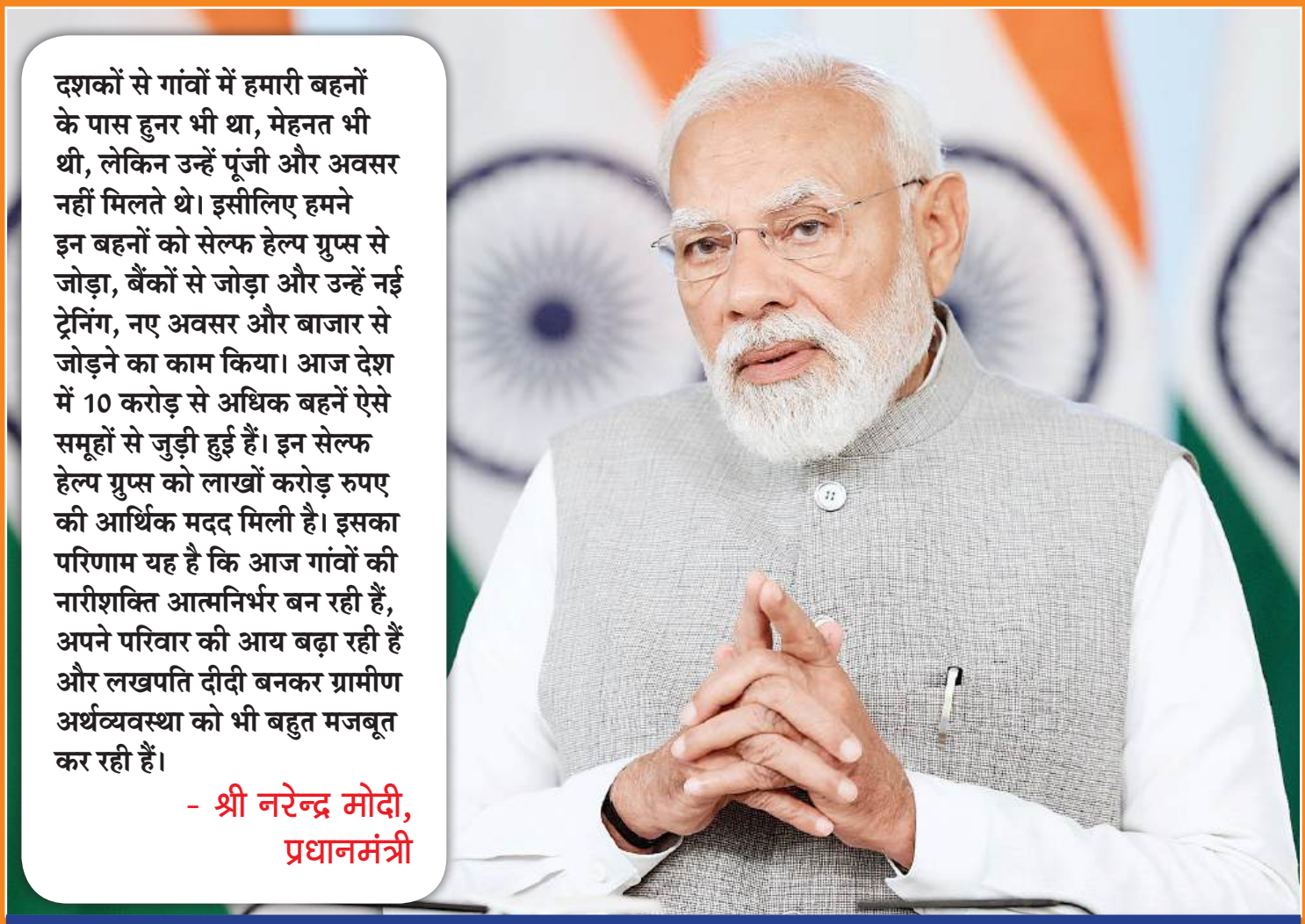

एनसीयूआई हाट, एनसीयूआई और कम प्रचलित सहकारी संस्थाओं के बीच नये आयाम स्थापित कर रहा है, जो उत्पादों की बिक्री और प्रदर्शनी के लिए एक सामान्य प्लेटफार्म उपलब्ध कराता है। अब एनसीयूआई हाट अपने नवीन ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से भी *'सहकार से समृद्धि'* को साकार करने के लिए उपर्युक्त वातावरण का निर्माण कर रहा है।

CEAS-LMS Portal

कोऑपरेटिव एक्सटेंशन एंड एडवाइजरी सर्विसेज लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम (**CEAS-LMS**) अपने तरह का पहला ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जो सहकारी सदस्यों को सहकारिता से जुड़ी सेवाओं की जानकारी देता है। यह तीन चरण में काम करता है:

1. **LMS:** लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के अंतर्गत पंजीकृत सदस्यों को प्रत्येक चरण की सहकार शिक्षा दी जाती है।
2. **QMS:** क्यूरी मैनेजमेंट सिस्टम एक ऐसा मंच है जहां उपयोगकर्ता सहकारिता से जुड़े अपने मुद्दे रख सकते हैं, जिससे उन्हें तुरंत गुणवत्ता परक सलाह मिल सके।
3. **CRC:** कोऑपरेटिव रिर्सोस सेंटर सभी हितधारकों का प्लेटफार्म है, जिसके माध्यम से सहकारिता से जुड़े सभी सदस्य जानकारियों का आदान प्रदान कर सके।

https://ncuicoop.education/

नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के लिए राजीव शर्मा द्वारा प्रकाशित और एनसीयूआई प्रिंटिंग प्रेस, बी-81, सेक्टर-80, नोएडा (उत्तर प्रदेश) में मुद्रित। संपादक : राजीव शर्मा

Postal Registration No: DLHIN/25/A0141
Published on 15.04.2024 Applied for Registration/ Exempted

भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ